

गरवी गुजरात

PRGI No. GJHIN/26/A1393

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM SURAT, AHMEDABAD, LUCKNOW

वर्ष : 01
अंक : 041
दि. 10.11.2026,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा
SURAT EDITION

नक्सलवाद की परिभाषा पर आमने-सामने राहुल और मोदी, विपक्ष के नेता ने फिर दी खुली बहस की चुनौती

राहुल बोले- कभी भी, कहीं भी चर्चा को तैयार, देशविरोधी कौन और विदेशी ताकतों के नियंत्रण में कौन, यह तय हो

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 'दिमागी नक्सल' शब्द का इस्तेमाल किए जाने के बाद देश की राजनीति में एक बार फिर आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री को खुली बहस की चुनौती देते हुए कहा कि वह किसी भी समय और किसी भी स्थान पर चर्चा के लिए तैयार हैं। राहुल ने सवाल उठाया कि आखिर देशविरोधी कौन है और किसके ऊपर विदेशी ताकतों का प्रभाव है, इसका फैसला बहस के जरिए होना चाहिए। उन्होंने अपनी चुनौती दोहराते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को उनके साथ आमने-सामने बैठकर इन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। इस बयान के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक टकराव और तेज होने के आसार हैं।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों को संबोधित करते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने प्रधानमंत्री के दिवाली संबोधन का उल्लेख करते हुए दावा किया कि जवानों के चेहरों से साफ दिखाई दे रहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री की बातों पर विश्वास नहीं किया। राहुल ने लिखा कि प्रधानमंत्री ने विपक्षी नेताओं को नक्सल करार दिया है, लेकिन उनकी चुनौती अब भी कायम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उनसे इस विषय पर बहस करें कि देश के खिलाफ कौन काम कर रहा है और किसे विदेशी ताकतें नियंत्रित कर रही हैं। राहुल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि वह कभी भी और कहीं भी चर्चा के लिए तैयार हैं। उनके मुताबिक, बहस के बाद प्रधानमंत्री में जवानों के सामने दोबारा खड़े होने का साहस नहीं रहेगा।

राहुल गांधी का यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संबोधन के बाद आया है, जिसमें उन्होंने नक्सलवाद के बदलते स्वरूप को लेकर सतर्क रहने की जरूरत बताई थी। प्रधानमंत्री ने रविवार को छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के करनपुर स्थित एक शिविर में सीआरपीएफ के जवानों के साथ दीपावली मनाई थी। इस दौरान उन्होंने सुरक्षाबलों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि



देश में हथियारबंद माओवादियों के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता मिली है, लेकिन नक्सलवाद का खतरा पूरी तरह समाप्त मान लेना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जंगलों में सक्रिय हथियारबंद नक्सलियों की ताकत कमजोर हुई है, लेकिन उनकी विचारधारा से प्रभावित तत्व अब भी अलग-अलग संगठनों और संस्थाओं में सक्रिय हो सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने ऐसे लोगों के लिए 'दिमागी नक्सल' शब्द का इस्तेमाल किया। उनका कहना था कि हथियारबंद नक्सली जंगलों से गायब हो रहे हैं, लेकिन उनकी विचारधारा से जुड़े लोग कई संगठनों में प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे तत्व संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री ने जवानों से कहा कि इस चुनौती को समझना और ऐसे लोगों की पहचान करना भी जरूरी है। उनके अनुसार, देश की सुरक्षा केवल सीमा और जंगलों में चलने वाले अभियानों तक सीमित नहीं है, बल्कि वैचारिक स्तर पर भी सतर्कता आवश्यक है।

मोदी ने अपने संबोधन में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में सीआरपीएफ, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और छत्तीसगढ़ पुलिस के योगदान का उल्लेख किया। बस्तर और आसपास के क्षेत्रों में लंबे समय से माओवादी गतिविधियां सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बनी रही हैं। इन इलाकों में सुरक्षाबलों ने लगातार अभियान चलाकर माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री ने जवानों के साहस, समर्पण और कठिन परिस्थितियों में निभाई जा रही जिम्मेदारियों की सराहना की। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि सुरक्षा अभियान में मिली उपलब्धियों के बावजूद किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए।

दरअसल, नक्सलवाद के मुद्दे पर केंद्र सरकार पिछले कुछ समय से लगातार अपनी उपलब्धियों का उल्लेख करती रही है। इसी वर्ष 31 मार्च को केंद्र सरकार ने दावा किया था कि देश नक्सलवाद के खतरे से मुक्त हो गया है। सरकार ने माओवादी नेताओं और कैडर के खिलाफ कार्रवाई, बड़ी संख्या में गिरफ्तारियों तथा सैकड़ों लोगों के आत्मसमर्पण को इस दिशा में बड़ी सफलता बताया था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी माओवादी हिंसा के खिलाफ अभियान को मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रभावी नीतियों का परिणाम बताया था। हालांकि, हालिया संबोधन में उन्होंने यह स्पष्ट किया कि हथियारबंद गतिविधियों में कमी आने का अर्थ यह नहीं है कि नक्सल विचारधारा से जुड़ी चुनौतियां भी पूरी तरह समाप्त हो गई हैं।

प्रधानमंत्री इससे पहले भी 'दिमागी नक्सल' की अवधारणा का उल्लेख कर चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अगस्त में दिए गए भाषण में उन्होंने कहा था कि जंगलों से हथियारबंद नक्सलवाद को पीछे धकेला गया है, लेकिन उसकी विचारधारा से प्रभावित लोग अब भी हिंसा और अराजकता को बढ़ावा देने के अवसर तलाश सकते हैं। सरकार का तर्क रहा है कि नक्सलवाद केवल हथियार उठाने वाले समूहों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके वैचारिक समर्थन और नेटवर्क पर भी ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी ओर, विपक्ष इस तरह की शब्दावली को राजनीतिक विरोधियों और सरकार की आलोचना करने वालों को निशाना बनाने का तरीका मान सकता है।

राहुल गांधी ने इसी राजनीतिक और वैचारिक बहस को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री को आमने-सामने चर्चा की चुनौती दी है। उन्होंने अपने बयान में राष्ट्रीय सुरक्षा, देशभक्ति और विदेशी प्रभाव जैसे मुद्दों को केंद्र में रखा। राहुल का कहना है कि देशविरोधी गतिविधियों और विदेशी ताकतों के प्रभाव को लेकर सार्वजनिक रूप से चर्चा होनी चाहिए, ताकि आरोपों की वास्तविकता सामने आ सके। हालांकि, प्रधानमंत्री की टिप्पणी और राहुल गांधी की प्रतिक्रिया के बीच बहस का विषय केवल नक्सलवाद तक सीमित नहीं रह गया है। अब यह विवाद राजनीतिक विरोध, राष्ट्रवाद की परिभाषा और लोकतांत्रिक संस्थाओं में असहमति की भूमिका तक पहुंचता दिखाई दे रहा है।

राजनीतिक दृष्टि से दोनों नेताओं के बयानों को आगामी दिनों में और तूल मिलने की संभावना है। भाजपा जहां नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई को अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करती रही है, वहीं कांग्रेस सरकार की नीतियों और राजनीतिक बयानबाजी पर सवाल उठाती रही है। राहुल गांधी की चुनौती ने इस विवाद को नया मोड़ दे दिया है। फिलहाल प्रधानमंत्री की ओर से राहुल गांधी की ताजा बहस की चुनौती पर कोई जवाब सामने आने की जानकारी नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि यह मामला केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहता है या दोनों पक्षों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा और नक्सलवाद की विचारधारा को लेकर कोई सार्वजनिक चर्चा भी आगे बढ़ती है।

तमिलनाडु में बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर सियासी घमासान, एक दिन में नौ हत्याओं का आरोप

तमिलनाडु में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने राज्य की टीवीके (तमिलगा वेत्री कषगम) सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि रविवार को प्रदेश में एक पुलिसकर्मी समेत नौ लोगों की हत्या हुई। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि आम नागरिकों के साथ पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं हैं। उदयनिधि ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय को निशाने पर लेते हुए उन्हें 'डमी मुख्यमंत्री' तक करार दिया और सरकार पर जनता की सुरक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया।

उदयनिधि स्टालिन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि त्योहार के दिन पटाखों की आवाज से अधिक धारदार हथियारों के टकराने की घटनाएं सुनाई दीं। उनके मुताबिक, प्रदेश में लगातार सामने आ रही आपराधिक घटनाएं प्रशासन की कमजोरी को उजागर करती हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि जब वे जेल का निरीक्षण करने जाते हैं तो कैदियों के फरार होने की घटनाएं सामने आती हैं और जब पुलिस थानों का दौरा करते हैं तो पुलिसकर्मियों पर हमले हो जाते हैं। उदयनिधि ने इसे सरकार की नाकामी बताते हुए कहा कि मौजूदा शासन में न तो आम जनता सुरक्षित है और न ही उसकी रक्षा करने वाले पुलिसकर्मी। उन्होंने अपनी पोस्ट में आरोप लगाया कि कमजोर प्रशासन के कारण अपराधियों में कानून का भय समाप्त हो गया है। उदयनिधि ने मुख्यमंत्री से राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर



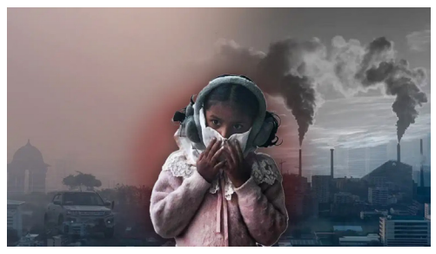
जवाब मांगा और कहा कि केवल अधिकारियों के निरीक्षण तथा जांच के आदेश देने से हालात नहीं सुधरेंगे। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपराध होने से पहले उन्हें रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।

विपक्ष के नेता ने विधानसभा के डिप्टी स्पीकर से जुड़ी एक कथित घटना को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि डिप्टी स्पीकर ने एक याचिकाकर्ता के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया तथा बाद में उसे धमकाकर वीडियो बयान जारी करने के लिए मजबूर किया गया। उदयनिधि ने इस घटना को लोकतांत्रिक व्यवस्था और नागरिक अधिकारों के लिहाज से गंभीर बताते हुए कहा कि किसी जनप्रतिनिधि द्वारा नागरिक के साथ इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह वास्तविक मुद्दों का जवाब देने के बजाय बार-बार विपक्षी दल डीएमके का नाम लेकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। इस मामले में भाजपा ने भी सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नारायणन तिरुपति ने विशेष उपनिरीक्षक (एसएसआई) सेंथिल कुमार की हत्या को बेहद गंभीर घटना बताते हुए कहा कि राज्य में पुलिसकर्मियों पर हमले बढ़ना चिंता का विषय है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि सड़क पर पटाखे फोड़ रहे और सोशल मीडिया के लिए रील बना रहे युवकों को रोकने की कोशिश करने पर एक पुलिस अधिकारी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। उनके अनुसार, यह घटना बताती है कि अपराधियों में पुलिस और प्रशासन का भय कम होता जा रहा है। भाजपा प्रवक्ता ने राज्य में हुई अन्य घटनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि अरियालुर में रात की गश्त पर तैनात होमगार्ड सी. वेंकटेशन ने सार्वजनिक स्थान पर शराब पी रहे तीन लोगों को रोकने का प्रयास किया था। इस दौरान उन पर हमला किया गया और चोटों के कारण उनकी मौत हो गई। इसी तरह चेंगलपट्टू के पास सेंगुनद्रम इलाके में एक सब-इंस्पेक्टर पर दरांती से हमला किए जाने की घटना सामने आई। बताया गया कि पुलिस अधिकारी थाने के पास हंगामा कर रहे एक नशे में धुत युवक को रोकने पहुंचे थे। हमले के दौरान उन्होंने अपनी वर्दी की बेल्ट की मदद से बचाव किया और बाद में हमलावर को काबू कर लिया। नारायणन तिरुपति ने थेनी जिला जेल में विचाराधीन कैदियों द्वारा जेल कर्मचारियों पर हमला करने और फरार होने की घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को नशे में धुत और हिंसक लोगों के हमलों का सामना करना पड़ा है।

जहरीली हवा से हर साल दुनिया में 80 लाख मौतें भारत में दम तोड़ रहे 20 लाख से अधिक लोग

नई दिल्ली। वायु प्रदूषण आज दुनिया के सामने खड़े सबसे गंभीर स्वास्थ्य संकटों में से एक बन चुका है। जहरीली हवा का खतरा अब किसी एक मौसम, शहर या त्योहार तक सीमित नहीं रह गया है। दिवाली पर पटाखों से निकलने वाले धुएं और बढ़ते प्रदूषण को लेकर हर साल बहस होती है, लेकिन हकीकत यह है कि साल के बाकी दिनों में भी करोड़ों लोग ऐसी हवा में सांस लेने को मजबूर हैं, जो धीरे-धीरे उनके शरीर को बीमार बना रही है। वाहनों का धुआं, कारखानों से निकलने वाला उत्सर्जन, कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र, खेतों में पराली जलाना, कचरे का दहन और घरों में खाना पकाने के लिए ठोस ईंधन का इस्तेमाल इस संकट को लगातार गंभीर बना रहे हैं। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2023 में दुनिया भर में वायु प्रदूषण के कारण करीब 80 लाख लोगों की मौत हुई। इनमें लगभग 20.06 लाख मौतें अकेले भारत में दर्ज की गईं। इसका अर्थ है कि वैश्विक स्तर पर प्रदूषण से होने वाली हर चार मौतों में से लगभग एक मौत भारत में हुई। ये आंकड़े देश के लिए गंभीर चेतावनी हैं और बताते हैं कि वायु प्रदूषण अब केवल पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा से जुड़ी बड़ी चुनौती बन चुका है।

भारत में वायु प्रदूषण की चर्चा अक्सर दिल्ली-एनसीआर, पराली जलाने और वाहनों से निकलने वाले धुएं तक सीमित रह जाती है, जबकि इसके कारण कहीं अधिक व्यापक हैं। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर की रिपोर्ट के



अनुसार, हवा में मौजूद सूक्ष्म कण पीएम 2.5 के प्रमुख स्रोतों में परिवहन, औद्योगिक गतिविधियां, बिजली उत्पादन, कृषि, घरेलू ईंधन, कचरा जलाना और जंगलों में लगने वाली आग शामिल हैं। इन सभी स्रोतों से निकलने वाले प्रदूषक वातावरण में मिलकर हवा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। दक्षिण एशिया वर्ष 2023 में दुनिया के सबसे अधिक पीएम 2.5 प्रदूषण का सामना करने वाले क्षेत्रों में शामिल रहा। भारत की बड़ी आबादी, तेजी से बढ़ता शहरीकरण, ऊर्जा की बढ़ती मांग और औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार इस समस्या को और जटिल बना रहे हैं। शहरों में वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ सड़कों पर धूल, निर्माण कार्यों से उड़ने वाले कण और औद्योगिक उत्सर्जन भी हवा को दूषित करते हैं। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी घरेलू ईंधन और कृषि गतिविधियों से होने वाला प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।

इस संकट का एक बड़ा और अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला पहलू घरों के भीतर होने वाला वायु प्रदूषण है। देश के कई हिस्सों में आज भी खाना पकाने के लिए लकड़ी, कोयला, उपले और दूसरे ठोस ईंधनों का इस्तेमाल किया जाता है। इन ईंधनों को जलाने से निकलने वाला धुआं रसोई और घर के दूसरे हिस्सों में फैल जाता है। सीमित वेंटिलेशन वाले घरों में रहने वाले परिवार लंबे समय तक इस धुएं के संपर्क में रहते हैं। महिलाओं और छोटे बच्चों पर इसका असर विशेष रूप से गंभीर हो सकता है, क्योंकि खाना पकाने के दौरान वे अक्सर रसोई के आसपास अधिक समय बिताते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ठोस ईंधन से निकलने वाला धुआं देश के बाहरी पीएम 2.5 प्रदूषण में भी करीब 30 प्रतिशत योगदान देता है। इससे स्पष्ट होता है कि वायु प्रदूषण की समस्या केवल सड़कों और कारखानों तक सीमित नहीं है, बल्कि घरों के भीतर इस्तेमाल होने वाले ईंधन और ऊर्जा के विकल्प भी इससे सीधे जुड़े हुए हैं।

हवा में मौजूद पीएम 2.5 कण आकार में इतने छोटे होते हैं कि सांस के साथ फेफड़ों की गहराई तक पहुंच सकते हैं। सामान्य धूल के बड़े कणों की तुलना में ये अधिक खतरनाक माने जाते हैं, क्योंकि शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा व्यवस्था इन्हें आसानी से बाहर नहीं निकाल पाती। लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने से फेफड़ों में सूजन पैदा हो सकती है और सांस लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।

परिसीमन विधेयकों के लिए बहुमत जुटाने में लगी सरकार? संसद सत्रावसान पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र का औपचारिक समापन नहीं होने को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का दावा है कि सरकार ने जानबूझकर सत्रावसान की प्रक्रिया पूरी नहीं की, ताकि गृह मंत्री अमित शाह को लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत जुटाने के लिए अतिरिक्त समय मिल सके। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार इस बहुमत के सहारे परिसीमन से जुड़े विधेयकों को पारित कराने की तैयारी कर रही है। पार्टी ने प्रस्तावित विधेयकों को देश की संसदीय और राजनीतिक व्यवस्था के लिए खतरनाक बताते हुए मांग की है कि परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर कोई भी निर्णय लेने से पहले सभी राजनीतिक दलों के साथ पारदर्शी चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने सोमवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर संसद सत्रावसान में हो रही देरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए 88 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक दोनों सदनों का औपचारिक सत्रावसान नहीं किया गया है। उनके अनुसार, यह संसद के इतिहास में अब तक का सबसे लंबा अंतराल है। उन्होंने इस स्थिति को असामान्य बताते हुए कहा कि सामान्य संसदीय परंपरा के अनुसार सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के कुछ ही दिनों के भीतर सत्रावसान की प्रक्रिया पूरी कर दी जाती है।

मानसून सत्र की अंतिम बैठक 13 अगस्त को हुई थी। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी। हालांकि, सदनों का औपचारिक सत्रावसान नहीं किया गया। जयराम रमेश ने संसदीय कार्यप्रणाली पर आधारित पुस्तक 'प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट' का हवाला देते हुए कहा कि आमतौर पर लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने और सत्रावसान के बीच दो से चार दिनों का अंतर रहता है। इससे पहले अधिकतम 28 दिनों का अंतर वर्ष 2015 के मानसून सत्र में दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति इन सामान्य संसदीय परंपराओं से काफी अलग है। कांग्रेस नेता ने वर्ष 2008 के मानसून सत्र का भी उल्लेख किया, जब सदन के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने और औपचारिक सत्रावसान के बीच 87 दिनों का अंतर रहा था। उन्होंने कहा कि इस बार 88 दिन बीतने के साथ ही पुराना रिकॉर्ड भी पीछे छूट गया है। जयराम रमेश के मुताबिक, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 19 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को लिखे पत्र में वर्ष 2008 के 87 दिनों के अंतर का उल्लेख किया था। अब सरकार के ही बताए आंकड़ों के आधार पर मौजूदा स्थिति उससे आगे निकल चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि इतने लंबे समय तक सत्रावसान की प्रक्रिया क्यों रोकी गई है। इस देरी के पीछे कांग्रेस ने राजनीतिक मंशा होने का आरोप लगाया है। जयराम रमेश ने दावा किया कि सरकार लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश कर रही है, ताकि परिसीमन से संबंधित विधेयकों को पारित कराया जा सके। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार आवश्यक संख्या बल हासिल करने के लिए राजनीतिक जोड़-तोड़ में लगी है।

एसआईटी की गिरफ्त से पहले मौत के आगोश में पहुंचा शराब माफिया मोहिन जायसवाल

देवास। मध्य प्रदेश के देवास जिले में पुलिस अधिकारी को ट्रक से कुचलकर मौत के घाट उतारने के सनसनीखेज मामले में आरोपी शराब माफिया मोहिन जायसवाल की मौत हो गई है। टीआई दिलीप पुरी गोस्वामी हत्याकांड की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) उसकी तलाश में जुटी थी। इसी बीच रविवार को गुजरात के अहमदाबाद में उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। बताया गया है कि उसे ब्रेन स्ट्रोक आया था। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। मोहिन की मौत की सूचना मिलने के बाद एसआईटी की टीम अस्पताल पहुंची और पूरे घटनाक्रम के संबंध में जानकारी जुटाई। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि उसकी तबीयत कब से खराब थी और वह अहमदाबाद में किन परिस्थितियों में रह रहा था।

यह मामला एक नवंबर की रात देवास जिले के खातेगांव थाना क्षेत्र में सामने आया था। इंदौर-बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैध शराब से भरे मिनी ट्रक को रोकने



की कोशिश करना टीआई दिलीप पुरी गोस्वामी के लिए जानलेवा साबित हुआ। पुलिस अधिकारी ने जब संदिग्ध मिनी ट्रक को रोकने का प्रयास किया तो उसमें सवार लोगों ने वाहन रोकने के बजाय उन्हें कुचल दिया और मौके से फरार हो गए। इस घटना में टीआई की मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी कुछ दूरी पर मिनी ट्रक छोड़कर भाग निकले। पुलिस अधिकारी की इस तरह हत्या किए जाने से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी और पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए एसआईटी का गठन किया। जांच टीम ने घटनास्थल से मिले साक्ष्यों, वाहन और अन्य सुरागों के आधार पर संदिग्धों की पहचान करने का प्रयास किया। जांच में सामने आया कि यह मामला केवल अवैध शराब की ढुलाई तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके पीछे शराब कारोबार से जुड़े लोगों का नेटवर्क भी सक्रिय था। इसी कड़ी में मोहिन जायसवाल का नाम सामने आया। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ के दौरान मोहिन को इस पूरे मामले से जुड़ा बताया था। इसके बाद एसआईटी उसकी तलाश में जुट गई थी।

कन्नौद एसडीओपी और एसआईटी में शामिल आदित्य तिवारी के अनुसार, मोहिन जायसवाल पिछले दो दिनों से बीमार था। एसआईटी की टीम अहमदाबाद में उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही थी। इसी दौरान रविवार को उसकी तबीयत अचानक अधिक बिगड़ गई। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसकी मौत की पुष्टि की। शुरुआती जानकारी के अनुसार, उसे ब्रेन स्ट्रोक आया था। हालांकि पुलिस अधिकारी ने स्पष्ट किया कि उसकी बीमारी, अस्पताल में भर्ती होने और मौत से जुड़े सभी तथ्यों की विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। एसआईटी ने अस्पताल पहुंचकर आवश्यक छानबीन शुरू कर दी है, ताकि घटनाक्रम की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सके। इस हत्याकांड में पुलिस ने मिनी ट्रक के चालक गजेंद्र उर्फ अक्कू और उसके सहयोगी धीरज को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। बताया गया है कि गिरफ्तारी के दौरान दोनों आरोपियों ने पुलिस से बचकर भागने की कोशिश की थी। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए गोली चलाई, जो उनके पैरों में लगी। इसके बाद दोनों को दोबारा पकड़कर हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान इन आरोपियों ने मोहिन जायसवाल का नाम लिया था। पुलिस अब तक मिली जानकारी के आधार पर यह पता लगाने में जुटी थी कि टीआई की हत्या की घटना में किसकी क्या भूमिका थी और अवैध शराब के कारोबार का संचालन किस तरह किया जा रहा था। जांच में यह बात भी सामने आई थी कि मोहिन जायसवाल शराब के ठेके में 30 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता था। इस जानकारी के बाद पुलिस की जांच का दायरा अवैध शराब के कारोबार और उससे जुड़े आर्थिक हितों तक भी पहुंच गया था। एसआईटी यह पता लगाने का प्रयास कर रही थी कि मिनी ट्रक में शराब कहां से लाई गई थी, उसे कहां पहुंचाया जाना था और इस नेटवर्क में अन्य कौन-कौन लोग शामिल थे। मोहिन की मौत के बाद जांच एजेंसियों के सामने अब यह चुनौती है कि उसके संपर्कों, कारोबार और संभावित भूमिका से जुड़े तथ्यों को अन्य आरोपियों तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट किया जाए। टीआई दिलीप पुरी गोस्वामी की हत्या ने पुलिस सुरक्षा और अवैध शराब के कारोबार पर नियंत्रण को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे। एक पुलिस अधिकारी की ड्यूटी के दौरान इस तरह हत्या किया जाना कानून-व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती के रूप में देखा गया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ शराब माफिया के नेटवर्क तक पहुंचने की कार्रवाई तेज कर दी थी।

सूचना

हमारा कार्यालय नववर्षाभिनंदन, भाई दूज और तीज त्योहार के उपलक्ष्य में 10, 11 और 12 नवम्बर 2026 को बंद रहेगा। इसलिए, समाचार पत्र 11, 12 और 13 नवम्बर को उपलब्ध नहीं होगा। अगला अंक 14 नवम्बर, 2026, शनिवार से यथावत प्रकाशित होगा।

- सम्पादक

दिवाली की रात पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में उछाल, 1200 स्थानों पर आग का दावा

नई दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर राजनीतिक घमासान एक बार फिर तेज हो गया है। दिवाली के दौरान पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में अचानक बढ़ोतरी होने का दावा करते हुए दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दिवाली के दिन पंजाब में खेतों में आग लगने की घटनाएं असामान्य रूप से बढ़ीं और इसके पीछे किसी सुनियोजित साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। कपिल मिश्रा ने भारत सरकार के सैटेलाइट आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि पांच, छह और सात नवंबर को पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं लगभग 100 से 125 के बीच थीं, लेकिन आठ नवंबर की शाम यह संख्या अचानक बढ़कर करीब 1200 तक पहुंच गई। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। सोमवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कपिल मिश्रा ने बताया कि दिवाली की शाम से ही पंजाब के अलग-अलग इलाकों से किसानों के फोन आने लगे थे। किसानों ने शिकायत की कि जब वे अपने परिवारों के साथ त्योहार मना रहे थे, उसी दौरान उनके खेतों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही थीं। शुरुआत में इन सूचनाओं पर विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन अलग-अलग क्षेत्रों से लगातार शिकायतें मिलने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार के सैटेलाइट आंकड़े मंगवाए गए। मंत्री के मुताबिक, इन आंकड़ों में दिवाली के दिन आग लगने की घटनाओं में अचानक और बड़ी वृद्धि दिखाई दी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पिछले दिनों घटनाओं की





संख्या सीमित थी तो एक ही दिन में यह आंकड़ा दस गुना से अधिक कैसे बढ़ गया? कपिल मिश्रा ने कहा कि सात नवंबर को लगभग 125 स्थानों पर पराली जलाने की घटनाएं दर्ज होने की जानकारी थी, जबकि छह नवंबर को यह संख्या करीब 100 और पांच नवंबर को भी लगभग इतनी ही बताई गई थी। इसके बावजूद आठ नवंबर की शाम अचानक करीब 1200 स्थानों पर आग लगने का दावा सामने आया। उन्होंने कहा कि यह सामान्य परिस्थितियों में होने वाली वृद्धि नहीं लगती और इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। मंत्री ने आशंका जताई कि किसानों के खेतों में जानबूझकर आग लगाकर पंजाब के किसानों, दिवाली के त्योहार और दिल्ली को बदनाम करने की कोशिश की गई हो सकती है। हालांकि, उन्होंने अपने आरोपों के समर्थन में किसी व्यक्ति या संगठन की भूमिका का अंतिम प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि जांच के माध्यम से सच्चाई सामने लाने की मांग की। उन्होंने पंजाब के किसानों की सराहना करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में किसान पराली जलाने से बचने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कई किसान वैकल्पिक तरीकों को अपनाकर खेतों में फसल अवशेषों का प्रबंधन कर रहे हैं। कुछ स्थानों पर परिस्थितियों के कारण आग लगने की घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन दिवाली के दिन अचानक इतनी बड़ी संख्या में घटनाएं सामने आना संदेह पैदा करता है। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी राजनीतिक विवाद का हिस्सा बनाकर बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। यदि खेतों में जानबूझकर आग लगाई गई है तो इसके पीछे शामिल लोगों की पहचान करना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में कपिल मिश्रा ने पंजाब के विभिन्न शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के कथित रूप से बेहद खराब स्तर पर पहुंचने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने दावा किया कि नौ नवंबर की सुबह मलोट में एक्यूआई 1238, अबोहर में 1307 और संगरूर में 1651 दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है। इन आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने सवाल किया कि पंजाब के शहरों में प्रदूषण की इतनी गंभीर स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? उन्होंने कहा कि केवल दिल्ली के प्रदूषण पर राजनीतिक बयानबाजी करने के बजाय पंजाब के किसानों और आम नागरिकों की परेशानी पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। संगरूर और बठिंडा जैसे इलाकों में प्रदूषण की स्थिति को लेकर उन्होंने भगवंत मान सरकार से जवाब मांगा।

मंत्री ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी के अन्य नेताओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि दिवाली से पहले पार

चाय पर चर्चा

जातीय गोलबंदी से सत्ता तक पहुंचने की कोशिश

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपने-अपने सामाजिक समीकरणों को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। सत्ता में दोबारा वापसी के लिए भाजपा जहां अपने पुराने मतदाता आधार को मजबूत बनाए रखने के साथ नए वर्गों तक पहुंच बनाने में जुटी है, वहीं समाजवादी पार्टी अपने पीडीए अभियान को व्यापक रूप देकर भाजपा के सामने मजबूत चुनौती खड़ी करना चाहती है। इस राजनीतिक खींचतान के केंद्र में जातीय भागीदारी, सामाजिक प्रतिनिधित्व और मतदाताओं की नाराजगी जैसे मुद्दे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 80 प्रतिशत वाला राजनीतिक दृष्टिकोण और अखिलेश यादव का 95 प्रतिशत आबादी को एकजुट करने का प्रयास प्रदेश की चुनावी राजनीति को नई दिशा दे सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। अलग-अलग चुनावों में राजनीतिक दलों ने इन्हीं समीकरणों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया और मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की रणनीति बनाई। भाजपा ने पिछले चुनावों में हिंदुत्व, विकास और कानून-व्यवस्था के मुद्दों के साथ गैर-यादव पिछड़े तथा गैर-जाटव दलित वर्गों के बीच अपनी पकड़ मजबूत की। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी लंबे समय तक यादव और मुस्लिम मतदाताओं के मजबूत समर्थन के सहारे चुनावी मैदान में उतरती रही। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी की छवि और सामाजिक आधार को बदलने का प्रयास किया है। पीडीए के माध्यम से वह पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को एक साझा राजनीतिक मंच पर लाना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ का 80 बनाम 20 प्रतिशत का फॉर्मूला भाजपा की राजनीतिक रणनीति का चर्चित हिस्सा रहा है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए इस संदेश को विपक्ष ने धार्मिक ध्रुवीकरण से जोड़कर देखा था। मुख्यमंत्री ने इसे विकास और सुशासन के समर्थकों तथा विरोधियों के बीच का विभाजन बताया था। भाजपा ने इस संदेश के जरिए अपने समर्थक वर्ग को एकजुट करने का प्रयास किया। अब 2027 के चुनाव में भी पार्टी इसी तरह के व्यापक राजनीतिक संदेश के माध्यम से अपने मतदाता आधार को मजबूत करने की कोशिश कर सकती है। हालांकि बदलते सामाजिक और राजनीतिक हालात में केवल पुराने नारों के सहारे चुनावी सफलता हासिल करना आसान नहीं होगा। अखिलेश यादव का 95 बनाम पांच प्रतिशत का संदेश इसी राजनीतिक रणनीति का जवाब माना जा रहा है। उनका जोर समाज के उन वर्गों को एकजुट करने पर है, जिन्हें वह सत्ता और प्रशासन में पर्याप्त भागीदारी से वंचित मानते हैं। पीडीए के जरिए समाजवादी पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि प्रदेश की बहुसंख्यक आबादी को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अधिक स्थान मिलना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस गठबंधन को केवल भाषणों और चुनावी सभाओं तक सीमित न रखकर बूथ स्तर तक प्रभावी बनाना है। इसके लिए उन्हें अलग-अलग जातीय समूहों के बीच विश्वास कायम करना होगा और उनके स्थानीय नेतृत्व को भी उचित स्थान देना होगा। इस बीच यूजीसी के दिशा-निर्देशों को लेकर सामान्य वर्ग के एक हिस्से में असंतोष की चर्चा ने राजनीतिक दलों को नई रणनीति बनाने का अवसर दिया है। भाजपा के लिए यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सामान्य वर्ग लंबे समय से उसका मजबूत समर्थक माना जाता रहा है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से जुड़े सीएसडीएस-लोकनीति के आंकड़ों में सामान्य वर्ग के लगभग 77 प्रतिशत मतदाताओं का भाजपा के पक्ष में मतदान करने का अनुमान सामने आया था। यदि किसी नीति या निर्णय को लेकर इस वर्ग में नाराजगी बढ़ती है तो उसका असर चुनावी समीकरणों पर पड़ सकता है। विपक्ष इस असंतोष को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकता है। हालांकि अभी यह देखना बाकी है कि इस मुद्दे का मतदाताओं पर कितना और कितने समय तक प्रभाव बना रहता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से यूजीसी के दिशा-निर्देशों के स्वरूप और संतुलन को लेकर जताई गई चिंताओं की चर्चा भी राजनीतिक हलकों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भाजपा के लिए संघ के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखना हमेशा से संगठनात्मक मजबूती का आधार रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में पार्टी के अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन के बाद सरकार और संगठन के बीच तालमेल को लेकर कई सवाल उठे थे। ऐसे में 2027 के चुनाव से पहले भाजपा नेतृत्व की कोशिश होगी कि किसी भी तरह की आंतरिक दूरी को समाप्त किया जाए। पार्टी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसके सहयोगी दलों और विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच समन्वय बना रहे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की गोरखपुर में हुई कोर कमेटी की बैठक को भी इसी चुनावी तैयारी के संदर्भ में देखा जा रहा है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी तथा संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह सहित वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। इसमें संगठन की स्थिति, सामाजिक समीकरणों और आगामी चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। भाजपा की रणनीति युवाओं, महिलाओं और प्रभावशाली सामाजिक समूहों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने की है।

ट्रंप की चुनावी हार से भारतीय अर्थव्यवस्था को नई उम्मीदें

अमेरिकी राजनीति में आए इस बदलाव से भारत के लिए अवसर जरूर पैदा हुए हैं, लेकिन इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए केवल अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुकूल होने का इंतजार करना पर्याप्त नहीं होगा। भारत को अपनी आर्थिक नीतियों, औद्योगिक क्षमता और निर्यात प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना होगा।



अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को मिली करारी शिकस्त ने वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य में नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। चुनाव परिणामों के बाद भारतीय शेयर बाजार में दिखाई दिया उछाल घरेलू निवेशकों के लिए दीपावली के उपहार से कम नहीं रहा। लंबे समय से वैश्विक अनिश्चितताओं, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और अंतरराष्ट्रीय तनाव के कारण दबाव झेल रहे भारतीय बाजार को इस घटनाक्रम से नई ऊर्जा मिली है। निवेशकों को उम्मीद है कि अमेरिकी राजनीति में बदले शक्ति संतुलन के कारण ट्रंप प्रशासन की मनमानी नीतियों पर कुछ अंकुश लगेगा और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में स्थिरता लौटने की संभावना बढ़ेगी। इसका लाभ भारत जैसे उभरते बाजारों को मिल सकता है। हालांकि इस उत्साह के पीछे केवल राजनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि तेल की कीमतों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) उद्योग में निवेश की दिशा और भारत की आर्थिक संभावनाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण कारण भी हैं।

अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी की सफलता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ट्रंप की नीतियों को लेकर अमेरिकी समाज का एक बड़ा वर्ग असंतुष्ट है। खासकर महंगाई, आयात शुल्क, ऊर्जा की कीमतों और सरकार के एकतरफा फैसलों को लेकर जनता में नाराजगी रही है। चुनाव में डेमोक्रेट्स ने इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया और मतदाताओं का समर्थन हासिल किया। अब कांग्रेस के दोनों सदनों में उनकी मजबूत स्थिति राष्ट्रपति ट्रंप के लिए नीतिगत फैसलों को आसानी से लागू करना कठिन बना सकती है। निवेशकों को लगता है कि इससे अमेरिका की आर्थिक नीतियों में अत्यधिक अनिश्चितता कम होगी। जब किसी बड़े देश की नीतियों को लेकर असमंजस बढ़ता है तो उसका असर पूरी दुनिया के वित्तीय बाजारों पर पड़ता है। इसके विपरीत राजनीतिक संतुलन और नीतिगत स्थिरता की उम्मीद निवेशकों का भरोसा बढ़ाती है।

इस चुनाव में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के डाटा सेंटर भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरे। पिछले कुछ वर्षों में एआइ तकनीक के तेजी से विस्तार के कारण अमेरिका सहित कई देशों में विशाल डाटा सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों में अत्याधुनिक सर्वर, कंप्यूटर चिप और अन्य तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल होता है। इनके संचालन के लिए भारी मात्रा में बिजली और पानी की आवश्यकता पड़ती है। अमेरिका के कई इलाकों में स्थानीय नागरिकों ने इन परियोजनाओं को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि डाटा सेंटरों के कारण बिजली की मांग बढ़ रही है, जल संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है और आम उपभोक्ताओं के लिए उपयोगिता सेवाओं की लागत बढ़ सकती है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस असंतोष को चुनावी मुद्दा बनाया और बड़े तकनीकी उद्योगों की जवाबदेही तथा पर्यावरणीय प्रभावों पर सवाल उठाए।

डेमोक्रेट्स की जीत के बाद यह आशंका बढ़ी है कि अमेरिका में डाटा सेंटरों के निर्माण और संचालन से संबंधित नियम अधिक सख्त किए जा सकते हैं। बिजली की खपत, जल संसाधनों के उपयोग और पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर कंपनियों पर अतिरिक्त शर्तें लागू हो सकती हैं। इससे एआइ क्षेत्र में बड़े निवेश की योजनाओं और भविष्य में होने वाले मुनाफे को लेकर निवेशकों की चिंताएं बढ़ी हैं। जिन कंपनियों के शेयरों की कीमतें एआइ से जुड़ी भविष्य की संभावनाओं के आधार पर तेजी से बढ़ी थीं, उनके मूल्यांकन पर अब सवाल उठने लगे हैं। निवेशक यह जानना चाहते हैं कि डाटा सेंटर, चिप निर्माण और सर्वर पर अरबों डॉलर खर्च करने वाली कंपनियां वास्तव में कितना लाभ कमा पाएंगी और इस भारी पूंजीगत निवेश की भरपाई कितने समय में होगी। इसी अनिश्चितता के कारण अमेरिकी तकनीकी कंपनियों के शेयरों में दबाव देखने को मिला।

इसका असर दूसरे देशों के शेयर बाजारों पर भी पड़ा, क्योंकि वैश्विक निवेश बाजार एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। अमेरिका की बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों में गिरावट आने पर दुनिया भर के निवेशक अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करते हैं। हालांकि भारतीय शेयर बाजार पर इसका प्रभाव अपेक्षाकृत सीमित रहा। इसकी एक वजह भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र का अलग कारोबारी मॉडल है। भारत की बड़ी आइटी कंपनियां मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर सेवाओं, डिजिटल समाधान, तकनीकी परामर्श और व्यावसायिक सेवाओं के माध्यम से आय अर्जित करती हैं। उन्हें एआइ के विकास के लिए अमेरिका और ताइवान की कंपनियों की तरह बड़े पैमाने पर चिप निर्माण अथवा डाटा सेंटरों के निर्माण में पूंजी लगाने की अनिवार्यता नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि भारतीय आइटी कंपनियों पर एआइ उद्योग में होने वाले बदलावों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उनका जोखिम निवेश और आय के स्वरूप के कारण अलग है।

यही वजह है कि वैश्विक निवेशक अब तकनीकी कंपनियों के ऊंचे मूल्यांकन और भारी पूंजीगत खर्च वाले कारोबार के साथ-साथ अपेक्षाकृत कम पूंजी आधारित सेवा क्षेत्र की संभावनाओं का भी आकलन कर रहे हैं। भारत का आइटी उद्योग लंबे समय से वैश्विक कंपनियों को तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराता रहा है। सॉफ्टवेयर विकास, साइबर सुरक्षा, क्लाउड सेवाएं, डाटा प्रबंधन और डिजिटल परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों की मजबूत मौजूदगी है। एआइ तकनीक के विस्तार से इन सेवाओं की मांग बढ़ने की संभावना भी है। इसलिए यदि वैश्विक निवेशक अत्यधिक जोखिम वाले तकनीकी शेयरों से पूंजी निकालकर दूसरे क्षेत्रों में निवेश करना चाहते हैं तो भारतीय आइटी और सेवा क्षेत्र उनके लिए आकर्षक विकल्प बन सकता है। हालांकि इसके लिए भारतीय कंपनियों को भी एआइ के बदलते स्वरूप के अनुरूप अपनी तकनीकी क्षमता और कारोबारी रणनीति मजबूत करनी होगी।

भारत के लिए सबसे बड़ी राहत ऊर्जा बाजार से मिल सकती है। देश अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात से पूरा करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में होने वाला उतार-चढ़ाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डालता है। कच्चा तेल महंगा होने से आयात बिल बढ़ता है, चालू खाते का घाटा बढ़ने की आशंका रहती है और रुपये पर दबाव पैदा होता है। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, परिवहन और उत्पादन लागत बढ़ने से महंगाई भी प्रभावित होती है। यदि अमेरिकी राजनीतिक घटनाक्रम के बाद ईरान के साथ तनाव कम होता है और पश्चिम एशिया में ऊर्जा आपूर्ति सामान्य होती है तो भारत को दोहरा लाभ मिल सकता है। एक ओर कच्चे तेल की कीमतों में राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर विदेशी मुद्रा पर पड़ने वाला दबाव भी कम हो सकता है।

पिछले कुछ समय से ईरान के साथ अमेरिका के टकराव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को अस्थिर बनाए रखा है। होर्मुज जलडमरूमध्य इस पूरे घटनाक्रम का सबसे संवेदनशील केंद्र रहा है। यह समुद्री मार्ग खाड़ी देशों से दुनिया के विभिन्न हिस्सों तक कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ जाती है। इसका असर केवल तेल उत्पादक और उपभोक्ता देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि परिवहन, विनिर्माण, विमानन, खाद्य उत्पादन और व्यापार की लागत पर भी पड़ता है। भारत के लिए यह स्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऊर्जा की बढ़ती कीमतें घरेलू उद्योगों से लेकर आम परिवारों के बजट तक को प्रभावित करती हैं। ऐसे में अमेरिका की राजनीति में आया बदलाव यदि ईरान के साथ तनाव कम करने का रास्ता खोलता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ी राहत मिल सकती है।

ट्रंप की चुनावी हार का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों से जुड़ा है। पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पाई है। ट्रंप प्रशासन ने आयात शुल्क को लेकर सख्त रुख अपनाया और कई देशों पर ऊंची दरों से शुल्क लगाने की नीति अपनाई। भारत ने भी अपने आर्थिक और व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी दबाव के सामने झुकने के बजाय बातचीत और अपने हितों की रक्षा करने का रास्ता चुना। इससे दोनों देशों के बीच कुछ मुद्दों पर असहमति बनी रही। अब अमेरिकी कांग्रेस में डेमोक्रेट्स की मजबूत स्थिति से व्यापार नीति को लेकर नई बहस शुरू हो सकती है। डेमोक्रेटिक पार्टी ट्रंप की एकतरफा टैरिफ नीति की आलोचक रही है और भारत के साथ आर्थिक सहयोग के महत्व को भी समझती है। ऐसे में कांग्रेस के भीतर से राष्ट्रपति प्रशासन पर व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने का दबाव बन सकता है।

यदि भारत और अमेरिका के बीच लंबित व्यापार समझौता अंतिम रूप लेता है तो दोनों देशों के कारोबारियों और निवेशकों को लाभ मिल सकता है। भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार में पहुंच आसान हो सकती है और विभिन्न क्षेत्रों में व्यापारिक बाधाएं कम होने की संभावना बनेगी। कपड़ा, रत्न एवं आभूषण, औषधि, इंजीनियरिंग उत्पाद और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों को इससे अवसर मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त अमेरिकी कंपनियों का भारत में निवेश बढ़ने से रोजगार और औद्योगिक विकास को भी प्रोत्साहन मिल सकता है। हालांकि यह मान लेना उचित नहीं होगा कि डेमोक्रेट्स की जीत के बाद व्यापार समझौता अपने आप हो जाएगा। अमेरिका में व्यापार नीति पर राष्ट्रपति के साथ-साथ कांग्रेस, उद्योग संगठनों और विभिन्न हित समूहों का भी प्रभाव रहता है। इसलिए भारत को अपने आर्थिक हितों के अनुरूप सावधानीपूर्वक बातचीत जारी रखनी होगी। भारतीय शेयर बाजार में बढ़ती दिलचस्पी का संबंध घरेलू निवेशकों के व्यवहार से भी है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में मध्यवर्ग का विस्तार हुआ है और बचत के पारंपरिक साधनों के साथ शेयर बाजार में निवेश की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। म्यूचुअल फंड और व्यवस्थित निवेश योजनाओं यानी एसआइपी के माध्यम से बड़ी संख्या में आम नागरिक शेयर बाजार से जुड़ रहे हैं। इन निवेशकों के लिए बाजार में लंबे समय तक बनी रहने वाली अनिश्चितता चिंता का विषय होती है।

टेक्नॉलॉजी

एयरटेल ग्राहकों की मौज, एक रिचार्ज पर दूसरा मुफ्त, 56 दिन तक मिलेगी सेवा

मोबाइल रिचार्ज पर खर्च कम करने की कोशिश कर रहे एयरटेल ग्राहकों के लिए कंपनी का एक खास ऑफर चर्चा में है। इसके तहत चुनिंदा प्रीपेड उपभोक्ताओं को एक रिचार्ज कराने पर दूसरा रिचार्ज मुफ्त मिल रहा है। कंपनी का यह बाय वन गेट वन फ्री ऑफर 349 रुपये और 399 रुपये वाले प्रीपेड प्लान पर उपलब्ध बताया जा रहा है। यदि किसी ग्राहक के एयरटेल थैंक्स एप में यह ऑफर दिखाई देता है तो वह एक बार भुगतान करके दो रिचार्ज का लाभ उठा सकता है। दोनों रिचार्ज की वैधता 28-28 दिन होने के कारण कुल 56 दिनों तक सेवा का लाभ मिल सकता है।

एयरटेल का यह ऑफर सभी ग्राहकों के लिए उपलब्ध नहीं है। इसे कंपनी ने चुनिंदा उपभोक्ताओं तक सीमित रखा है और इसकी उपलब्धता की जानकारी एयरटेल थैंक्स एप पर ही मिल सकती है। इसलिए रिचार्ज करने से पहले ग्राहकों को अपने एप में संबंधित प्लान और ऑफर की शर्तें जरूर जांच लेनी चाहिए। खास बात यह है कि दोनों प्लान में डेटा, कॉलिंग और एसएमएस के साथ कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी दी जा रही हैं। 349 रुपये वाले प्रीपेड प्लान में ग्राहकों को प्रतिदिन दो जीबी हाई-स्पीड डेटा मिलता है। इसके अलावा एयरटेल के 5जी नेटवर्क की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में पात्र ग्राहकों को अनलिमिटेड 5जी डेटा का लाभ भी दिया जाता है। प्लान में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड लोकल और एसटीडी कॉलिंग की सुविधा शामिल है। इसके साथ ही प्रतिदिन 100 एसएमएस भेजने की सुविधा भी मिलती है। इस प्लान की वैधता 28 दिनों की है। यदि ग्राहक को बाय वन गेट वन ऑफर मिलता है और दूसरा रिचार्ज भी सफलतापूर्वक लागू होता है, तो उसे कुल 56 दिनों तक रिचार्ज का लाभ मिल सकता है। इस प्लान की एक अन्य विशेषता इसमें मिलने वाला एडोबी एक्सप्रेस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है। जानकारी के मुताबिक, ग्राहकों को 12 महीने के लिए यह सुविधा दी जा रही है, जिसकी बताई गई कीमत करीब चार हजार रुपये है। इसके जरिए उपयोगकर्ता फोटो, पोस्टर, सोशल मीडिया ग्राफिक्स और अन्य रचनात्मक सामग्री तैयार करने के लिए प्रीमियम टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा प्लान में फ्री हेलोट्यून्स और एयरटेल सेफ जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं।

एयरटेल सेफ के तहत ग्राहकों को डिजिटल सुरक्षा से जुड़ी सुविधाएं मिलती हैं। इनमें स्पैम कॉल की पहचान और अलर्ट, संदिग्ध लिंक को ब्लॉक करने तथा ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के लिए एआइ आधारित फ्रॉड अलर्ट जैसी सुविधाएं शामिल बताई गई हैं। डिजिटल लेनदेन और ऑनलाइन गतिविधियों के बढ़ते इस्तेमाल के बीच इस तरह की सुविधाएं ग्राहकों के लिए उपयोगी हो सकती हैं। हालांकि इन सेवाओं की वास्तविक उपलब्धता और शर्तों की पुष्टि रिचार्ज से पहले एप में करनी चाहिए। कंपनी के 399 रुपये वाले प्रीपेड प्लान पर भी इसी तरह का ऑफर बताया जा रहा है। इस प्लान की वैधता भी 28 दिनों की है। इसमें अनलिमिटेड लोकल और एसटीडी कॉलिंग के साथ प्रतिदिन 100 एसएमएस भेजने की सुविधा मिलती है। इस प्लान की प्रमुख खासियत अनलिमिटेड डेटा का लाभ है। इसमें प्रतिदिन डेटा इस्तेमाल की कोई निश्चित सीमा नहीं बताई गई है। हालांकि अनलिमिटेड डेटा के इस्तेमाल पर लागू होने वाली नेटवर्क, उचित उपयोग नीति और अन्य शर्तों को समझना जरूरी है। 4जी और 5जी नेटवर्क पर मिलने वाली सुविधाएं क्षेत्र और डिवाइस की क्षमता के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं। इस ऑफर का लाभ लेने के लिए ग्राहकों को सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में एयरटेल थैंक्स एप खोलना होगा। इसके बाद प्रीपेड रिचार्ज सेक्शन में जाकर 349 रुपये और 399 रुपये वाले प्लान देखने होंगे। यदि किसी प्लान के साथ '1+1 रिचार्ज फ्री' का टैग दिखाई देता है तो संबंधित ग्राहक इस ऑफर के लिए पात्र हो सकता है। इसके बाद एप पर दिए गए निर्देशों के अनुसार रिचार्ज की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यदि यह टैग दिखाई नहीं देता है तो संभव है कि ग्राहक के नंबर पर फिलहाल यह सुविधा उपलब्ध न हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑफर सीमित अवधि और चुनिंदा ग्राहकों के लिए बताया जा रहा है। इसलिए केवल प्रचार के आधार पर यह मान लेना सही नहीं होगा कि हर एयरटेल उपभोक्ता को दूसरा रिचार्ज मुफ्त मिलेगा। ग्राहकों को भुगतान करने से पहले यह भी जांचना चाहिए कि दूसरा रिचार्ज किस तरह लागू होगा, उसकी वैधता कब से शुरू होगी और दोनों रिचार्ज से मिलने वाले लाभों पर कौन-सी शर्तें लागू हैं। कुल मिलाकर, जिन ग्राहकों के एप में यह ऑफर उपलब्ध है, उनके लिए यह कम खर्च में लंबी अवधि तक मोबाइल सेवाओं का लाभ लेने का अच्छा मौका हो सकता है।

विचार प्रवाह

बिहार पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा की नई तारीख घोषित, 17 नवंबर से डाउनलोड होंगे प्रवेश पत्र

बिहार में पुस्तकालयाध्यक्ष बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) ने विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा 2026 की तारीख में बदलाव कर दिया है। पहले यह परीक्षा 22 नवंबर से आयोजित की जानी थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों के चलते अब इसकी शुरुआत 23 नवंबर 2026 से होगी। परीक्षा कार्यक्रम में हुए इस बदलाव के बाद अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी और परीक्षा से जुड़ी योजनाओं में संशोधन करना होगा। बिहार बोर्ड ने प्रवेश पत्र जारी करने की तारीख भी घोषित कर दी है। इसके अनुसार परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार 17 नवंबर से अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र निर्धारित तिथि पर आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए उन्हें अपना लॉगिन विवरण दर्ज करना होगा। प्रवेश पत्र परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य दस्तावेज है। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि इसे जारी होते ही डाउनलोड कर लें और उसमें दर्ज सभी जानकारियों की सावधानीपूर्वक जांच करें।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sletregistration.cbrt.co.in पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध एडमिट कार्ड से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद मांगी गई लॉगिन जानकारी दर्ज कर सबमिट करना होगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रवेश पत्र स्क्रीन पर दिखाई देगा। अभ्यर्थी इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले एडमिट कार्ड में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना जरूरी होगा। यदि नाम, आवेदन संख्या, परीक्षा केंद्र या अन्य किसी विवरण में त्रुटि दिखाई देती है तो अभ्यर्थियों को समय रहते संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए।

बिहार विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा 2026 कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी माध्यम से आयोजित की जाएगी। परीक्षा में अभ्यर्थियों से कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना होगा। प्रश्नपत्र हल करने के लिए उम्मीदवारों को कुल 150 मिनट यानी ढाई घंटे का समय मिलेगा। इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रखा गया है। इसका अर्थ है कि गलत उत्तर देने पर अभ्यर्थियों के प्राप्त अंकों में कटौती नहीं की जाएगी। हालांकि परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए उम्मीदवारों को सभी प्रश्नों को सावधानीपूर्वक हल करना चाहिए और समय का उचित प्रबंधन करना होगा।

परीक्षा में सफल होने के लिए बिहार बोर्ड ने अलग-अलग आरक्षित और अनारक्षित श्रेणियों के लिए न्यूनतम अर्हता अंक निर्धारित किए हैं। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता अंक 45.5 प्रतिशत निर्धारित किए गए हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम 42.5 प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता अंक 40 प्रतिशत रखे गए हैं। इन निर्धारित अंकों को प्राप्त करने वाले उम्मीदवार परीक्षा की अर्हता पूरी कर सकेंगे। परीक्षा की तारीख में बदलाव के बाद अभ्यर्थियों के पास तैयारी के लिए उपलब्ध समय को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति तैयार करने का अवसर है। उम्मीदवारों को अब बचे हुए समय में पाठ्यक्रम का दोहराव, महत्वपूर्ण विषयों का अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चूंकि परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी, इसलिए मॉक टेस्ट के माध्यम से ऑनलाइन प्रश्न हल करने का अभ्यास भी उपयोगी रहेगा। साथ ही ढाई घंटे की परीक्षा में समय का सही इस्तेमाल करने की आदत विकसित करना जरूरी है।

अभ्यर्थियों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के बिना प्रवेश नहीं मिलेगा। एडमिट कार्ड के साथ आवश्यक पहचान पत्र और बोर्ड की ओर से बताए गए अन्य दस्तावेज भी साथ रखने होंगे। परीक्षा से संबंधित दिशा-निर्देशों, केंद्र और रिपोर्टिंग समय की जानकारी प्रवेश पत्र पर उपलब्ध होगी। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे किसी भी अफवाह या अपुष्ट सूचना पर भरोसा करने के बजाय बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट और परीक्षा पोर्टल से ही नवीनतम जानकारी प्राप्त करें।

फैक्ट ऑफ द डे

टीपू सुल्तान: अदम्य साहस, सैन्य कौशल और प्रशासनिक नवाचारों की अनोखी विरासत

अठारहवीं शताब्दी का भारतीय इतिहास ऐसे अनेक शासकों और योद्धाओं की गाथाओं से भरा है, जिन्होंने अपने साहस, नेतृत्व और दूरदर्शिता से इतिहास में अलग पहचान बनाई। इन्हीं में मैसूर के शासक सुल्तान फ़तेह अली साहब टीपू का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इतिहास में वह टीपू सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध हैं। अंग्रेजी सत्ता के विस्तार के दौर में उन्होंने जिस दृढ़ता के साथ अपने राज्य की स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा का प्रयास किया, उसने उन्हें भारतीय इतिहास का चर्चित व्यक्तित्व बना दिया। वह केवल युद्धभूमि के योद्धा नहीं थे, बल्कि प्रशासन, सैन्य तकनीक, कृषि, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में भी कई प्रयोग करने वाले शासक थे। उनकी पहचान एक ऐसे शासक के रूप में बनी, जिसने बदलते समय की चुनौतियों को समझते हुए अपने राज्य को मजबूत बनाने की कोशिश की।

टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को देवनहल्ली में हुआ था। उनके पिता हैदर अली मैसूर राज्य की सेना में एक सैनिक के रूप में कार्य करते थे। अपनी सैन्य क्षमता, राजनीतिक समझ और पराक्रम के बल पर उन्होंने धीरे-धीरे सत्ता में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया और वर्ष 1761 में मैसूर के वास्तविक शासक बन गए। टीपू की माता का नाम फखरुन्निसा था। बचपन से ही टीपू को सैन्य प्रशिक्षण, घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल की शिक्षा दी गई। पिता के साथ रहते हुए उन्होंने शासन और कूटनीति की बारीकियां भी सीखीं। हैदर अली अपने बेटे की वीरता और युद्धक



क्षमता से प्रभावित थे। इसी कारण उन्हें शेर-ए-मैसूर की उपाधि से भी जोड़ा जाता है। टीपू सुल्तान ने अपने पिता के साथ कई सैन्य अभियानों में हिस्सा लिया और कम उम्र में ही युद्ध के मैदान का अनुभव हासिल कर लिया था। वर्ष 1782 में हैदर अली का निधन होने के बाद उन्होंने मैसूर की सत्ता संभाली। उस समय दक्षिण भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी शक्ति तेजी से बढ़ा रही थी। अंग्रेजों का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपने प्रभाव में लाना और व्यापारिक हितों के साथ राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना था। टीपू सुल्तान ने इस विस्तारवादी नीति का विरोध किया। उनका मानना था कि यदि अं

गुजरात के तीन शहरों में बैंकों को बम से उड़ाने की धमकी, दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट भी निशाने पर

सूरत। गुजरात में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। राज्य के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा में कई बैंकों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। धमकी भरे संदेशों में केवल बैंक ही नहीं, बल्कि अहमदाबाद मेट्रो और 21 तारीख को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रस्तावित पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को भी निशाना बनाने की चेतावनी दी गई है। ईमेल में कॉन्सर्ट में शामिल होने वाले लोगों को अपने बच्चों को कार्यक्रम में नहीं भेजने की धमकी भी दी गई है। एक साथ तीन शहरों में बैंकों को निशाना बनाए जाने और बड़े सार्वजनिक आयोजन का जिक्र होने से सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड की टीमें संबंधित स्थानों पर पहुंचीं। एहतियात के तौर पर बैंकों को खाली कराया गया और परिसरों के चप्पे-चप्पे की तलाशी ली गई। फिलहाल किसी विस्फोटक सामग्री की पुष्टि नहीं हुई है और धमकी भरे ईमेल भेजने वाले की पहचान के लिए साइबर क्राइम की मदद से जांच की जा रही है।

अहमदाबाद में नवरंगपुरा इलाके की बैंक ऑफ इंडिया शाखा को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिला। संदेश में बैंक के साथ 21 तारीख को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट और अहमदाबाद मेट्रो में विस्फोट करने की चेतावनी भी दी गई थी। ईमेल की जानकारी मिलते ही बैंक प्रशासन ने पुलिस को सूचित किया। इसके बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंचीं। बैंक परिसर में मौजूद कर्मचारियों और अन्य लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षा जांच शुरू की गई। मेट्रो और कॉन्सर्ट से संबंधित धमकी को देखते हुए संबंधित सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी सतर्क किया गया। बड़े सार्वजनिक आयोजन को लेकर धमकी मिलने से आयोजकों और सुरक्षा एजेंसियों के



सामने अतिरिक्त सतर्कता बरतने की चुनौती खड़ी हो गई है।

सूरत में भी घोड़दौड़ रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा को धमकी भरा ईमेल मिला। यह इलाका शहर के व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्रों में शामिल है, जहां दिनभर बड़ी संख्या में लोगों और वाहनों की आवाजाही रहती है। बैंक के आधिकारिक ईमेल खाते पर धमकी भरा संदेश मिलने के बाद प्रबंधन ने बिना देरी किए पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वॉड, डॉग स्क्वॉड और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गईं। सुरक्षा के मद्देनजर बैंक के भीतर मौजूद कर्मचारियों को बाहर निकाला गया और ग्राहकों की आवाजाही रोक दी गई। इसके बाद सुरक्षा टीमों ने बैंक के विभिन्न हिस्सों की तलाशी ली। बैंक परिसर और आसपास के क्षेत्र में भी सतर्कता बरती गई, ताकि किसी संभावित खतरे को समय रहते टाला जा सके। दिवाली के त्योहार के दौरान घोड़दौड़ रोड जैसे व्यस्त इलाके में धमकी मिलने से आसपास के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में भी चिंता फैल गई। पुलिस ने बैंक परिसर की जांच के साथ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई। धमकी भरे ईमेल की तकनीकी जांच के लिए साइबर क्राइम टीम को भी शामिल किया गया है। जांच एजेंसियां ईमेल के स्रोत, उसके तकनीकी विवरण और आईपी एड्रेस सहित उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर संदेश भेजने वाले तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि अलग-अलग शहरों में भेजे गए ईमेल के पीछे एक ही व्यक्ति या समूह का हाथ है अथवा इसके लिए अलग-अलग माध्यमों का इस्तेमाल किया गया है।

वडोदरा में भी दो बैंकों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। शहर के रावपुरा रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया और सयाजीगंज इलाके की सूरज प्लाजा बिल्डिंग में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा को धमकी भरे ईमेल मिले। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी दोनों स्थानों पर पहुंचे। सुरक्षा के लिहाज से बैंकों में मौजूद कर्मचारियों और ग्राहकों को बाहर निकाला गया तथा परिसरों में लोगों की आवाजाही रोक दी गई। इसके बाद बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड ने दोनों बैंक शाखाओं की गहन तलाशी ली। आसपास के क्षेत्रों में भी पुलिस ने सतर्कता बरती और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी।

बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारी एस.के. त्यागी ने बताया कि बैंक की जीमेल आईडी पर धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ था। संदेश मिलने के बाद बैंक प्रबंधन ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। एहतियात के तौर पर पूरे स्टाफ को बाहर निकालकर बैंक परिसर खाली करा दिया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंचकर अपनी प्रक्रिया के अनुसार जांच कर रही है। सुरक्षा एजेंसियों की ओर से जांच पूरी होने तक बैंक परिसरों में सतर्कता बरती गई। इस तरह की धमकियों के कारण सामान्य बैंकिंग गतिविधियां भी प्रभावित होती हैं और कर्मचारियों तथा ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्राथमिकता बन जाता है।

तीनों शहरों में एक ही अवधि के दौरान धमकी भरे ईमेल मिलने से जांच एजेंसियां इनके आपसी संबंधों की भी पड़ताल कर रही हैं। साइबर क्राइम टीम ईमेल के तकनीकी स्रोत, आईपी एड्रेस, डिजिटल पहचान और अन्य उपलब्ध जानकारियों का विश्लेषण कर रही है। जांच का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि क्या सभी धमकी भरे संदेश एक ही ईमेल खाते या किसी साझा नेटवर्क से भेजे गए हैं। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि धमकी देने का उद्देश्य दहशत फैलाना था या इसके पीछे कोई वास्तविक आपराधिक साजिश है। फिलहाल जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है।

गौरतलब है कि इससे पहले 6 नवंबर को गुजरात हाई कोर्ट और मुख्यमंत्री कार्यालय को भी बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने की सूचना सामने आई थी। अब तीन शहरों के बैंक, अहमदाबाद मेट्रो और दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को लेकर धमकी मिलने से सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। लगातार सामने आ रहे ऐसे संदेशों के बीच सार्वजनिक स्थलों, सरकारी संस्थानों, बैंक परिसरों और बड़े आयोजनों की सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस ईमेल भेजने वाले की पहचान और धमकियों की वास्तविकता का पता लगाने में जुटी है। जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को देने की अपील की है।

दिवाली की आतिशबाजी बनी आग की वजह सूरत में एक रात में 150 कॉल से मचा हड़कंप

सूरत। दीपावली के उल्लास और आतिशबाजी के बीच सूरत शहर में पटाखों की चिंगारियों ने कई जगहों पर आग लगने की घटनाओं को जन्म दिया। रॉकेट और अन्य पटाखों से निकली चिंगारियां रिहायशी इमारतों की बालकनी, खुले प्लॉट और कूड़े के ढेर तक पहुंचीं, जिससे शहर के अलग-अलग इलाकों में आग लगने की घटनाएं सामने आईं। त्योहार की रात जहां लोग दीप जलाकर और आतिशबाजी कर खुशियां मना रहे थे, वहीं दूसरी ओर दमकल विभाग के कर्मचारियों को आग बुझाने के लिए लगातार दौड़ लगानी पड़ी। फायर विभाग के कंट्रोल रूम में पूरी रात आग लगने की सूचनाएं आती रहीं। एक ही रात में विभाग को कुल 150 कॉल मिले, जिसके चलते दमकलकर्मियों को लगातार सक्रिय रहना पड़ा।

जानकारी के अनुसार, आग लगने की अधिकांश घटनाएं रिहायशी सोसाइटियों, ऊंची इमारतों की बालकनी और खुले स्थानों पर जमा कचरे में हुईं। लोगों की ओर से छोड़े गए रॉकेट और पटाखों की जलती चिंगारियां कई बार इमारतों की बालकनी में रखे सामान पर गिर गईं। वहीं, खुले प्लॉट में जमा सूखे कचरे ने भी आग पकड़ ली। देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगीं



और कई स्थानों पर धुएं के गुबार दिखाई देने लगे। अचानक आग लगने से स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई। कई जगहों पर लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग फैलने की आशंका को देखते हुए दमकल विभाग को सूचना दी गई।

दिवाली की रात एक साथ बड़ी संख्या में आग की घटनाओं की सूचना मिलने से फायर विभाग के कंट्रोल रूम पर भी दबाव बढ़ गया। शहर के अलग-अलग हिस्सों से लगातार कॉल आने के कारण दमकल की गाड़ियों को एक के बाद एक घटनास्थलों के लिए रवाना करना पड़ा। कई इलाकों में एक ही समय पर आग लगने की सूचना मिलने से संसाधनों का प्रबंधन चुनौतीपूर्ण हो गया। कुछ स्थानों पर दमकल की टीमों को पहुंचने में देरी हुई, जिसके दौरान आग ने आसपास रखे सामान और संपत्तियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग पर पूरी तरह काबू पाने के लिए कर्मचारियों को लंबे समय तक पानी की बौछार करनी पड़ी।

रिहायशी इमारतों की बालकनी में रखे पुराने सामान, कपड़े, प्लास्टिक और अन्य ज्वलनशील वस्तुओं के कारण आग तेजी से फैलने का खतरा बना रहा। इसी तरह खुले प्लॉट में जमा सूखे पत्ते और कूड़ा भी पटाखों की चिंगारी से आग पकड़ने का कारण बने। इन घटनाओं ने एक बार फिर त्योहारों के दौरान आतिशबाजी करते समय सावधानी बरतने की जरूरत को सामने ला दिया। खासकर ऊंची इमारतों और घनी आबादी वाले इलाकों में रॉकेट और तेज गति से उड़ने वाले पटाखों के इस्तेमाल से आसपास के घरों और संपत्तियों को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है।

आग की लगातार मिल रही सूचनाओं के बीच सूरत के सभी फायर स्टेशनों के कर्मचारी पूरी रात अलर्ट रहे। दमकल की टीमें अलग-अलग स्थानों पर पहुंचकर आग बुझाने और स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी रहीं। करीब 150 कॉल मिलने के बावजूद विभाग के लगातार प्रयासों से किसी भी घटना में मौत या गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं मिली। हालांकि, कुछ स्थानों पर घरों और अन्य सामान को नुकसान पहुंचने से लोगों को आर्थिक क्षति उठानी पड़ी।

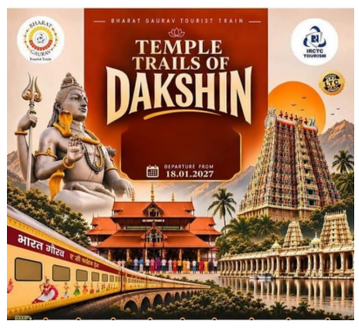
दीपावली पर आतिशबाजी के दौरान हुई इन घटनाओं ने अग्नि सुरक्षा को लेकर सतर्कता की अहमियत भी उजागर की है। पटाखे जलाते समय खुले और सुरक्षित स्थान का चयन करना, इमारतों की बालकनी में ज्वलनशील सामान नहीं रखना तथा कूड़े के ढेर के आसपास आतिशबाजी से बचना बेहद जरूरी है। थोड़ी सी लापरवाही न केवल संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकती है, बल्कि लोगों की जान को भी खतरे में डाल सकती है। सूरत में एक ही रात में मिले 150 कॉल इस बात का संकेत हैं कि त्योहार की खुशियों के बीच सुरक्षा संबंधी सावधानियों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है।

दक्षिण भारत के नौ तीर्थों की यात्रा कराएगी आईआरसीटीसी की भारत गौरव ट्रेन

मुंबई। दक्षिण भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को करीब से देखने की इच्छा रखने वाले पर्यटकों के लिए भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) विशेष यात्रा की तैयारी कर रहा है। आईआरसीटीसी के पश्चिम क्षेत्र, मुंबई की ओर से 'टेम्पल ट्रेल्स ऑफ दक्षिण' नाम से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन संचालित की जाएगी। यह ट्रेन 18 जनवरी 2027 को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) से अपनी यात्रा शुरू करेगी। 11 रात और 12 दिनों के इस विशेष टूर पैकेज में यात्रियों को दक्षिण भारत के नौ प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। इस यात्रा के लिए पैकेज की शुरुआती कीमत 20,420 रुपये प्रति यात्री निर्धारित की गई है।

आईआरसीटीसी की इस विशेष पहल के माध्यम से यात्रियों को एक ही यात्रा में दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिरों, समुद्र तटों, ऐतिहासिक धरोहरों और सांस्कृतिक केंद्रों को देखने का अवसर मिलेगा। यात्रा में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के प्रमुख स्थलों को शामिल किया गया है। इनमें गोकर्ण, मुरुडेश्वर, गुरुवायुर, रामेश्वरम, मदुरै, कन्याकुमारी, तिरुचिरापल्ली, कांचीपुरम और महाबलीपुरम प्रमुख हैं। इन स्थानों पर धार्मिक आस्था से जुड़े मंदिरों के साथ प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के दर्शनीय स्थलों का भी भ्रमण कराया जाएगा।

यात्रा के दौरान सबसे पहले कर्नाटक के प्रसिद्ध तीर्थ एवं समुद्री पर्यटन स्थल गोकर्ण और



मुरुडेश्वर का आकर्षण देखने को मिलेगा। गोकर्ण में यात्रियों को महाबलेश्वर मंदिर में दर्शन के साथ प्रसिद्ध ओम बीच घूमने का अवसर मिलेगा। भगवान शिव को समर्पित महाबलेश्वर मंदिर धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। वहीं, मुरुडेश्वर में समुद्र तट के किनारे स्थित भगवान शिव का भव्य मंदिर और विशाल शिव प्रतिमा पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहेगी। समुद्र और पहाड़ियों के बीच स्थित यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है।

इसके बाद यात्रा में केरल के गुरुवायुर मंदिर को शामिल किया गया है। भगवान श्रीकृष्ण को समर्पित गुरुवायुर मंदिर देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में गिना जाता है। यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इसके बाद तमिलनाडु के रामेश्वरम में श्री रामनाथस्वामी मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। चार धाम यात्रा के प्रमुख तीर्थों में शामिल रामेश्वरम का धार्मिक महत्व देशभर में प्रसिद्ध है। यहां के विशाल गलियारे और मंदिर की स्थापत्य कला श्रद्धालुओं के साथ पर्यटकों को भी आकर्षित करती है। इसी क्षेत्र में स्थित धनुषकोडी का भ्रमण भी पैकेज का हिस्सा होगा। समुद्र के बीच स्थित यह क्षेत्र अपनी भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण विशेष पहचान रखता है।

यात्रा का अगला प्रमुख पड़ाव मदुरै होगा, जहां यात्रियों को प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। अपनी भव्य द्रविड़ स्थापत्य शैली, ऊंचे गोपुरम और बारीक शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध यह मंदिर दक्षिण भारत की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद पर्यटक कन्याकुमारी पहुंचेंगे, जहां कुमारी अम्मन मंदिर, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, गांधी मंडपम और सनसेट पॉइंट जैसे प्रमुख स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी समुद्र के मनोहारी दृश्यों और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के अद्भुत नजारों के लिए प्रसिद्ध है।

इस विशेष टूर में तिरुचिरापल्ली और तंजावुर के धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों को भी शामिल किया गया है। तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथस्वामी मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे, जो भगवान विष्णु को समर्पित प्रमुख वैष्णव तीर्थों में से एक है। इसके साथ तंजावुर मंदिर का भ्रमण भी यात्रा कार्यक्रम में रखा गया है। चोलकालीन स्थापत्य कला और ऐतिहासिक महत्व के कारण तंजावुर का मंदिर दक्षिण भारत की गौरवशाली विरासत का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है।

इसके बाद पर्यटक कांचीपुरम पहुंचेंगे। मंदिरों के शहर के रूप में प्रसिद्ध कांचीपुरम में कामाक्षी अम्मन मंदिर, एकाम्बरेश्वर मंदिर और श्री वरदराजा पेरुमल मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। यह शहर धार्मिक आस्था के साथ अपनी प्राचीन संस्कृति, मंदिर वास्तुकला और पारंपरिक रेशमी साड़ियों के लिए भी जाना जाता है। यात्रा के अंतिम प्रमुख पड़ावों में महाबलीपुरम शामिल है, जहां पर्यटकों को प्रसिद्ध शोर मंदिर और कृष्णा बटरबॉल देखने का अवसर मिलेगा। समुद्र तट के किनारे स्थित शोर मंदिर प्राचीन पल्लवकालीन स्थापत्य कला का शानदार नमूना है। वहीं, विशाल चट्टान पर असंतुलित दिखाई देने वाली कृष्णा बटरबॉल पर्यटकों के बीच खास आकर्षण रखती है।

आईआरसीटीसी ने यात्रियों की सुविधा और बजट को ध्यान में रखते हुए तीन श्रेणियों में पैकेज तैयार किए हैं। इकोनॉमी श्रेणी में स्लीपर क्लास से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए प्रति व्यक्ति किराया 20,420 रुपये रखा गया है। स्टैंडर्ड श्रेणी में थर्ड एसी का किराया 32,770 रुपये और कंफर्ट श्रेणी में सेकंड एसी का किराया 42,940 रुपये निर्धारित किया गया है। पांच से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए भी विशेष पैकेज दरें उपलब्ध कराई गई हैं। अलग-अलग श्रेणियों के माध्यम से यात्री अपनी सुविधा और बजट के अनुसार विकल्प चुन सकेंगे। पैकेज में केवल रेल यात्रा ही नहीं, बल्कि पूरे भ्रमण के दौरान आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था भी शामिल है।

किसी की बद्दुआ से नहीं बच सकते, कर्मों का हिसाब इसी जन्म में देना होगा : हर्ष संघवी

सूरत। विक्रम संवत 2083 के नववर्ष के आगमन पर गुजरात के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री हर्ष संघवी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं देने के साथ ही उन्हें कर्तव्य, ईमानदारी और मानवीय संवेदनाओं का महत्वपूर्ण संदेश दिया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और जवानों के साथ आयोजित विशेष नववर्ष मिलन कार्यक्रम में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वर्दी की ताकत का इस्तेमाल जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए होना चाहिए, न कि किसी आम नागरिक को परेशान करने के लिए। यदि कोई गरीब व्यक्ति उम्मीद लेकर पुलिस थाने पहुंचता है और उसे न्याय के बजाय निराशा मिलती है, तो यह केवल विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल नहीं है, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी से पीछे हटना भी है। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि किसी की हाय लोगे तो उसका हिसाब यहीं भुगतना पड़ेगा। इंसान अपने गलत कामों को अधिकारियों, बड़े पदों पर बैठे लोगों और यहां तक कि सरकार से भी छिपा सकता है, लेकिन अपने कर्मों के परिणाम से कभी नहीं बच सकता। कार्यक्रम के दौरान हर्ष संघवी ने दीपावली के अवसर पर शहर और राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिन-रात ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान जब अधिकांश लोग अपने परिवार के साथ खुशियां मनाते हैं, उस समय पुलिस के जवान सड़कों, चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर तैनात रहकर आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। उनके कारण नागरिक बिना किसी डर के त्योहार मना पाते हैं। पुलिसकर्मियों की यह जिम्मेदारी केवल ड्यूटी का हिस्सा नहीं, बल्कि समाज के प्रति उनके समर्पण और सेवा भावना का परिचायक है। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना आसान काम नहीं होता। भीड़भाड़, यातायात का दबाव, बाजारों में लोगों की आवाजाही और विभिन्न आयोजनों के बीच पुलिसकर्मियों को लगातार सतर्क रहना पड़ता है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को जिस तरह निभाया, वह प्रशंसा के योग्य है। उप मुख्यमंत्री ने केवल पुलिस विभाग ही नहीं, बल्कि दीपावली के दौरान आम जनता की सुविधा और सुरक्षा में योगदान देने वाले अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी विशेष रूप से धन्यवाद दिया। उन्होंने एसटी बसों के ड्राइवरों और कंडक्टरों का उल्लेख करते हुए कहा कि त्योहार के समय बड़ी संख्या में लोग अपने घरों और परिवारों तक पहुंचने के लिए सार्वजनिक परिवहन का सहारा लेते हैं। ऐसे में बस चालकों और परिचालकों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वे लंबे समय तक काम करते हैं और कई बार अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने का अवसर भी नहीं मिल पाता। इसी तरह आग लगने की घटनाओं के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर बचाव कार्य करने वाले फायर ब्रिगेड के



कर्मचारियों और शहर को स्वच्छ बनाए रखने वाले सफाईकर्मियों के योगदान को भी उन्होंने महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी शहर की व्यवस्था केवल बड़े अधिकारियों या जनप्रतिनिधियों से नहीं चलती, बल्कि हर स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों की मेहनत से व्यवस्था मजबूत होती है। पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान संघवी ने सरकारी आवासों और पुलिस थानों में स्वच्छता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी आवास भी किसी के अपने घर की तरह होते हैं और वहां रहने वाले कर्मचारियों को उनकी साफ-सफाई और रखरखाव की जिम्मेदारी उसी भावना से निभानी चाहिए। सार्वजनिक परिसर में गंदगी फैलाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। उन्होंने पान-मावा खाकर दीवारों, सीढ़ियों और अन्य स्थानों पर थूकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। उनका कहना था कि पुलिस विभाग से जुड़े परिसरों में अनुशासन और स्वच्छता का वातावरण दिखाई देना चाहिए, क्योंकि आम नागरिक जब पुलिस थाने या सरकारी कार्यालय में पहुंचता है, तो वहां की व्यवस्था से भी विभाग की छवि बनती है। उन्होंने अधिकारियों को पुलिस आवासीय परिसरों में स्वच्छता समितियां बनाने और नियमित रूप से साफ-सफाई की निगरानी करने की सलाह दी। साथ ही बच्चों के खेलने के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित करने पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि पुलिसकर्मी दिन-रात अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में उनके परिवारों, विशेषकर बच्चों के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराना भी जरूरी है। आवासीय परिसरों में साफ-सफाई, बच्चों के लिए खेलने की जगह और आवश्यक सुविधाएं होने से पुलिस परिवारों का जीवन बेहतर बन सकता है। उन्होंने पुलिस थानों के शौचालयों और पूरे परिसर को हर समय स्वच्छ रखने के निर्देश देते हुए कहा कि थाने में आने वाला आम नागरिक सम्मानजनक और साफ वातावरण का हकदार है। किसी फरियादी को गंदगी या अव्यवस्था के बीच अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए।

कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान संघवी ने विनम्रता का संदेश देते हुए कहा कि वह पुलिसकर्मियों को आशीर्वाद देने नहीं, बल्कि उनसे और जनता से आशीर्वाद लेने आए हैं। पुलिस कमिश्नर के संबोधन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी उम्र अभी ऐसी नहीं है कि वह किसी को आशीर्वाद दें। उन्होंने कहा, "मैं आशीर्वाद देने वाला नहीं, बल्कि लोगों का आशीर्वाद लेने वाला व्यक्ति हूं। मेरी पूरी जिंदगी लोगों के आशीर्वाद पर टिकी है।" इस बात के माध्यम से उन्होंने यह संदेश देने का प्रयास किया कि पद और अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण जनता का विश्वास और सहयोग है। किसी भी व्यक्ति को अपने पद के कारण अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझना चाहिए। हर्ष संघवी ने अपने काम करने के तरीके के बारे में भी अधिकारियों से खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें बड़े अधिकारी की तरह आदेश देने के बजाय टीम के सदस्य के रूप में सभी के साथ मिलकर काम करना पसंद है। किसी भी विभाग की सफलता तभी संभव है, जब उसके अधिकारी और कर्मचारी एक-दूसरे पर भरोसा करते हुए साझा जिम्मेदारी निभाएं। उन्होंने स्वीकार किया कि काम के दौरान कभी-कभी सख्ती करनी पड़ती है और अनुशासन बनाए रखने के लिए कठोर निर्णय भी लेने होते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी के प्रति मन में दुर्भावना रखी जाए। उन्होंने कहा कि उनके मन में किसी के लिए बुरी भावना नहीं रही है और आगे भी वह इसी सोच के साथ काम करते रहेंगे। उनका संदेश था कि प्रशासनिक सख्ती का उद्देश्य व्यवस्था सुधारना होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति को अपमानित या परेशान करना। अपने संबोधन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उन्होंने पुलिसकर्मियों की नैतिक जिम्मेदारी को लेकर रखा। संघवी ने कहा कि पुलिस की वर्दी पहनने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि उसके सामने आने वाला हर नागरिक किसी न किसी उम्मीद के साथ थाने पहुंचता है। कई बार गरीब, कमजोर और साधारण परिवारों के लोग अपनी समस्या लेकर पुलिस के पास आते हैं। उनके पास प्रभाव, पैसा या किसी बड़े अधिकारी तक पहुंचने का साधन नहीं होता। ऐसे में पुलिसकर्मी का व्यवहार ही उनके लिए न्याय की पहली उम्मीद बनता है। यदि किसी व्यक्ति की शिकायत को गंभीरता से नहीं सुना जाता, उसे अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है या उसके साथ अन्याय होता है, तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को आगाह किया कि किसी गरीब की परेशानी को छोटा समझने की गलती न करें। आम नागरिक की पीड़ा को समझना और उसकी शिकायत पर उचित कार्रवाई करना पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी है। उन्होंने कर्मों के परिणाम का उल्लेख करते हुए कहा कि विभाग के भीतर किसी अधिकारी या कर्मचारी का गलत व्यवहार कुछ समय तक छिपा रह सकता है। बड़े पदों पर बैठे लोगों को भी इसकी जानकारी न हो, ऐसा संभव है। यहां तक कि गृह मंत्री से भी किसी गलत काम को छिपाया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति अपनी अंतरात्मा और कर्मों से बच नहीं सकता। किसी जरूरतमंद को परेशान करना, उसके अधिकारों का हनन करना या उसकी मजबूरी का फायदा उठाना ऐसा आचरण है, जिसका परिणाम किसी न किसी रूप में सामने आता है। उन्होंने कहा कि किसी की बद्दुआ का हिसाब अगले जन्म में चुकाने की बात कहकर उसे टालना ठीक नहीं है, बल्कि इंसान को अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। इसलिए हर पुलिसकर्मी को अपने व्यवहार और फैसलों को लेकर आत्ममंथन करना चाहिए। संघवी ने पुलिसकर्मियों से यह भी आग्रह किया कि वे केवल सरकारी प्रोटोकॉल और औपचारिकताओं तक खुद को सीमित न रखें। प्रशासनिक व्यवस्था में नियम और प्रोटोकॉल का अपना महत्व है, लेकिन मानवीय संवेदनाओं को उससे कम नहीं आंका जा सकता। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी भी एक परिवार का हिस्सा हैं और उन्हें अपने परिवार के साथ समय बिताने का प्रयास करना चाहिए। लगातार काम के दबाव के बीच परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाना भी जरूरी है। इसी तरह जनता के साथ व्यवहार करते समय केवल पद, अधिकार और नियमों को सामने रखने के बजाय सामने वाले व्यक्ति की परिस्थिति को भी समझना चाहिए। किसी नागरिक की समस्या का समाधान संवेदनशीलता और सम्मान के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों और जवानों से अपनी अंतरात्मा पर हाथ रखकर यह सोचने की अपील की कि वे जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी कितनी ईमानदारी से निभा रहे हैं। उनका कहना था कि पुलिस सेवा का वास्तविक सम्मान तभी है, जब आम नागरिक बिना भय के थाने पहुंच सके और उसे भरोसा हो कि उसकी बात सुनी जाएगी। पुलिस की छवि केवल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई से नहीं बनती, बल्कि आम लोगों के साथ उसके रोजमर्रा के व्यवहार से भी तय होती है। जनता का विश्वास जीतना किसी भी पुलिस बल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कार्यक्रम के अंत में उप मुख्यमंत्री ने पूरी पुलिस फोर्स के सामूहिक प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें गर्व है कि पुलिस विभाग एक मजबूत टीम के रूप में जनता के हित में काम कर रहा है। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को विक्रम संवत 2083 के नववर्ष की शुभकामनाएं दीं और उम्मीद जताई कि आने वाले वर्ष में भी पुलिस बल इसी समर्पण, अनुशासन और सेवा भावना के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। उनका संदेश साफ था कि वर्दी का असली सम्मान उसके अधिकारों में नहीं, बल्कि उस भरोसे में है जो आम नागरिक पुलिस से करता है। किसी की मदद करना, उसकी पीड़ा सुनना और उसे न्याय दिलाने के लिए ईमानदारी से प्रयास करना ही पुलिस सेवा की सबसे बड़ी पहचान होनी चाहिए।

दिल्ली के जीबी रोड पर कामकाजी वर्ग की महिलाओं के मताधिकार से वंचित होने का दावा: "क्या हमारे वोट गंदे हैं?"

(निडर, निष्पक्ष और तटस्थ छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत

क्या हमें, एक संप्रभु राष्ट्र के नागरिक होने के नाते, मानव जाति के साथ भेदभाव रहित व्यवहार करने की संवैधानिक प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए या नहीं? शरीर को तृप्ति देने के लिए शरीर के सिवा कुछ नहीं है, और यह एक "अपधर्म" है जिसे हमें स्वीकार करना ही होगा, भले ही हम इसे पसंद न करें।

संविधान के लिए, वेश्यावृत्ति करके अपना पेट भरने की कोशिश करने वाली महिला उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि देश का राष्ट्रपति, नालियाँ साफ करने वाला सफाईकर्मी, चिलचिलाती धूप में खदान में काम करने वाला मजदूर, सर्दी, धूप या बारिश की परवाह किए बिना खेत जोतने वाला किसान, और अरबों रुपये कमाने वाला व्यापारी या उद्योगपति। इन सभी की तरह, उसे भी भारतीय नागरिक के रूप में प्राप्त अमूल्य "अधिकार" प्राप्त है कि वह



अपनी पसंद की पार्टी या उम्मीदवार को

एसजी हाईवे पर 464 करोड़ का एलिवेटेड ब्रिज शुरू, गांधीनगर क्षेत्र में सात साल में हुए 25 हजार करोड़ के विकास कार्य

अहमदाबाद और गांधीनगर की कनेक्टिविटी को मिलेगी नई रफ्तार, दो लाख से अधिक वाहन चालकों को रोजाना राहत मिलने की उम्मीद; नशे के खिलाफ गुजरात में 1033 हेल्पलाइन की पहल

अहमदाबाद। गुजरात में बुनियादी ढांचे के विस्तार और शहरी यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में सोमवार को अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की गई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सरखेज-गांधीनगर (एसजी) हाईवे पर 464 करोड़ रुपये की लागत से तैयार एलिवेटेड ब्रिज का लोकार्पण किया। इसके साथ ही अहमदाबाद शहर और जिले में करीब 1,024 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। इस अवसर पर अमित शाह ने बताया कि गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में पिछले सात वर्षों के दौरान लगभग 25 हजार करोड़ रुपये के विकास कार्य पूरे किए गए हैं। उन्होंने गुजरात को नशामुक्त बनाने के अभियान के तहत 1033 हेल्पलाइन शुरू करने की पहल का भी उल्लेख किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को मकान आवंटित करने के लिए कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ की प्रक्रिया भी आयोजित की गई।

एसजी हाईवे पर बने नए एलिवेटेड ब्रिज को अहमदाबाद की यातायात व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण परियोजना माना जा रहा है। करीब 4.03 किलोमीटर लंबे इस छह लेन के ब्रिज का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने कराया है। इसमें दोनों दिशाओं में तीन-तीन लेन बनाई गई हैं, जिससे वाहनों को व्यस्त चौराहों और ट्रैफिक सिग्नलों पर रुकने की आवश्यकता कम होगी। शहर के पश्चिमी हिस्से में तेजी से बढ़ती आबादी, आवासीय सोसायटियों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और औद्योगिक गतिविधियों के कारण एसजी हाईवे पर वाहनों का दबाव लगातार बढ़ रहा था। सुबह और शाम के व्यस्त समय में इस मार्ग पर लंबा जाम लगना आम समस्या बन गई थी। ऐसे में एलिवेटेड कॉरिडोर शुरू होने से यातायात के एक बड़े हिस्से को वैकल्पिक और निर्बाध मार्ग मिलने की उम्मीद है।



इस ब्रिज से प्रतिदिन दो लाख से अधिक वाहन चालकों को लाभ मिलने का अनुमान है। अब तक एसजी हाईवे के संबंधित हिस्से से गुजरने में यातायात की स्थिति के अनुसार लगभग 30 से 40 मिनट तक लग जाते थे। एलिवेटेड मार्ग का उपयोग करने वाले वाहन चालकों के लिए यह समय घटकर करीब पांच से सात मिनट रह जाने की संभावना जताई गई है। हालांकि वास्तविक समय की बचत वाहनों की संख्या, प्रवेश और निकास बिंदुओं तथा यातायात की स्थिति पर निर्भर करेगी। इसके शुरू होने से खासकर उन लोगों को राहत मिल सकती है, जिन्हें रोजाना अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच आवागमन करना पड़ता है। नौकरी, कारोबार, शिक्षा और अन्य कार्यों के लिए इस मार्ग का इस्तेमाल करने वाले हजारों लोगों के लिए यात्रा पहले की तुलना में अधिक सुगम होने की उम्मीद है।

एलिवेटेड ब्रिज का प्रभाव केवल एसजी हाईवे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे आसपास के प्रमुख जंक्शनों पर भी यातायात का दबाव कम होने की संभावना है। कर्णावती क्लब जंक्शन, प्रह्लादनगर चौराहा, वाईएमसीए क्लब क्रॉसिंग और साणंद सर्कल जैसे व्यस्त स्थानों पर वाहनों की आवाजाही को व्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है। परियोजना की खासियत यह है कि एलिवेटेड कॉरिडोर से लंबी दूरी के वाहन गुजर सकेंगे, जबकि ब्रिज के नीचे स्थानीय यातायात पहले की तरह संचालित होगा। इससे स्थानीय वाहन चालकों और हाईवे से होकर दूसरे शहरों की ओर जाने वाले वाहनों के बीच होने वाला टकराव कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही चौराहों पर रुकने और बार-बार गति धीमी करने की जरूरत घटने से ईंधन की बचत और यात्रा समय में कमी की भी उम्मीद है।

गांधीनगर और अहमदाबाद से राजकोट, भावनगर, सुरेंद्रनगर तथा सौराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों की ओर जाने वाले वाहन चालकों को इस परियोजना का लाभ मिलने की संभावना है। औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण साणंद जीआईडीसी की ओर आने-जाने वाले वाहनों के लिए भी आवागमन सुगम हो सकता है। साणंद क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों और कारोबारी गतिविधियों के विस्तार के साथ मालवाहक वाहनों की आवाजाही बढ़ी है। ऐसे में हाईवे पर निर्बाध यातायात उपलब्ध होना उद्योगों की लॉजिस्टिक्स व्यवस्था के लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है। मालवाहक वाहनों के समय पर पहुंचने से परिवहन लागत और देरी कम करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा शहर के पश्चिमी हिस्से में रहने वाले नागरिकों को भी रोजमर्रा के आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नौ हजार से अधिक आवासों के आवंटन के लिए कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ की प्रक्रिया भी आयोजित की गई। इस प्रक्रिया का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को निर्धारित व्यवस्था के तहत मकानों का आवंटन करना है। शहरी क्षेत्रों में बढ़ती आबादी और आवास की मांग को देखते हुए किफायती आवास उपलब्ध कराना सरकार की प्रमुख योजनाओं में शामिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर और अन्य पात्र वर्गों के परिवारों को अपना घर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ के जरिए आवंटन प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है। नौ हजार से अधिक आवासों से जुड़ी यह प्रक्रिया अहमदाबाद के उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है, जो लंबे समय से अपने घर का इंतजार कर रहे हैं।

अमित शाह ने इस अवसर पर गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में पिछले सात वर्षों के दौरान हुए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इस अवधि में करीब 25 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाएं पूरी की गई हैं। इन कार्यों में बुनियादी ढांचे, सड़क संपर्क, आवास, नागरिक सुविधाओं और क्षेत्रीय विकास से जुड़े विभिन्न प्रयास शामिल हैं। तेजी से विकसित हो रहे अहमदाबाद-गांधीनगर क्षेत्र में बढ़ती आबादी और आर्थिक गतिविधियों के अनुरूप सुविधाओं का विस्तार महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों शहरों के बीच बेहतर सड़क संपर्क, आवासीय सुविधाओं और अन्य आधारभूत परियोजनाओं से क्षेत्रीय विकास को गति देने का प्रयास किया जा रहा है। एसजी हाईवे का एलिवेटेड ब्रिज भी इसी व्यापक विकास प्रक्रिया का हिस्सा है।

कार्यक्रम के दौरान गुजरात को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से 1033 हेल्पलाइन शुरू करने की पहल की जानकारी भी दी गई। नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार और उनके सेवन से जुड़ी समस्याओं पर नियंत्रण के लिए नागरिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। हेल्पलाइन के माध्यम से नशे से संबंधित गतिविधियों की सूचना संबंधित एजेंसियों तक पहुंचाने का उद्देश्य है। इससे पुलिस और प्रशासन को ऐसी गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाने में सहायता मिल सकती है। नशे की समस्या का प्रभाव केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहता, बल्कि परिवार, युवाओं और सामाजिक व्यवस्था पर भी पड़ता है। इसलिए नशे के खिलाफ अभियान में जागरूकता, रोकथाम, कानून का पालन और प्रभावित लोगों के पुनर्वास जैसे पहलुओं पर भी ध्यान देना आवश्यक है। अहमदाबाद में आयोजित कार्यक्रम के जरिए सड़क परिवहन, आवास और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को एक साथ सामने रखा गया। एसजी हाईवे पर एलिवेटेड ब्रिज के शुरू होने से जहां शहर के पश्चिमी हिस्से में यातायात व्यवस्था को राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं आवास योजना के तहत हजारों परिवारों को घर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में सात वर्षों के दौरान 25 हजार करोड़ रुपये के विकास कार्यों का उल्लेख और नशे के खिलाफ हेल्पलाइन की पहल भी कार्यक्रम के प्रमुख बिंदु रहे। आने वाले समय में इन परियोजनाओं का वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि उनका संचालन, रखरखाव और नागरिकों तक सुविधाओं की पहुंच कितनी प्रभावी रहती है।

जरूरतमंद बच्चों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर एडवोकेट प्रीति जे. जोशी ने मनाई दिवाली

सूरत। दीपावली का पर्व खुशियों, रोशनी और आपसी प्रेम का प्रतीक है। त्योहार की असली खुशी तब और बढ़ जाती है, जब इन खुशियों को समाज के उन बच्चों के साथ साझा किया जाए, जिन्हें अक्सर ऐसे अवसरों पर विशेष सुविधाएं नहीं मिल पातीं। इसी भावना के साथ एडवोकेट प्रीति जे. जोशी ने इस वर्ष दिवाली का त्योहार स्लम इलाके में स्थित दीन सहायक विद्या मंदिर स्कूल के बच्चों के साथ मनाया। उन्होंने वेसू वॉटर टैंक पर बच्चों के बीच पहुंचकर उनके साथ त्योहार की खुशियां साझा कीं और उन्हें दिवाली की सौगात देकर उनके चेहरों पर मुस्कान बिखेरी।

इस अवसर पर प्रीति जे. जोशी ने बच्चों को पटाखे, चॉकलेट, बिस्कुट, ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट स्टिक वितरित किए। उपहार पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे और उनके बीच उत्साह का माहौल बन गया। बच्चों ने भी पूरे उल्लास के साथ दिवाली का आनंद लिया। इस पहल के माध्यम से उन्होंने यह संदेश देने का प्रयास किया कि त्योहार केवल अपने परिवार और परिचितों के बीच खुशियां मनाने तक सीमित नहीं होने चाहिए, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग को इसमें शामिल करना चाहिए।



इस सामाजिक पहल में गुजरात बार काउंसिल (बीसीजी) के सदस्य तथा गुजरात हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रीजि जिग्नेश जोशी भी शामिल हुए। उनके साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी बच्चों के बीच पहुंचकर त्योहार मनाया और इस आयोजन को यादगार बनाया। सभी ने बच्चों के साथ समय बिताया और उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दीं।

इस मौके पर प्रीति जे. जोशी ने कहा कि त्योहार समाज के हर वर्ग के लिए होते हैं। खुशियों पर किसी एक वर्ग का अधिकार नहीं है। दीपावली जैसे पर्व का वास्तविक महत्व तभी है, जब हम अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल करें। जरूरतमंद बच्चों के साथ त्योहार मनाने से न केवल उन्हें अपनापन महसूस होता है, बल्कि समाज में आपसी प्रेम, सहयोग और समानता की भावना भी मजबूत होती है। उन्होंने सभी से अपील की कि त्योहारों के अवसर पर जरूरतमंदों और बच्चों के बीच पहुंचकर उनके साथ खुशियां साझा करें।

इस आयोजन ने यह संदेश दिया कि दीपावली की रोशनी केवल घरों और बाजारों को ही नहीं, बल्कि लोगों के जीवन को भी रोशन कर सकती है। किसी बच्चे को दिया गया छोटा-सा उपहार और उसके चेहरे पर आई मुस्कान भी त्योहार की सबसे बड़ी सौगात बन सकती है।

छठ पर्व पर अहमदाबाद से राजगीर के लिए चलेगी अनारक्षित सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन

अहमदाबाद। छठ पूजा के अवसर पर घर जाने वाले यात्रियों की बढ़ती संख्या और ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने अहमदाबाद और बिहार के राजगीर के बीच अनारक्षित सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। विशेष किराये पर संचालित होने वाली यह ट्रेन दोनों दिशाओं में यात्रियों को अतिरिक्त रेल सुविधा उपलब्ध कराएगी। त्योहार के दौरान नियमित ट्रेनों में सीटों और सामान्य डिब्बों में जगह को लेकर होने वाली परेशानी को कम करने के उद्देश्य से रेलवे ने यह व्यवस्था की है। ट्रेन संख्या 09427 अहमदाबाद-राजगीर स्पेशल 10 नवंबर 2026 को अहमदाबाद से रवाना होगी, जबकि वापसी में ट्रेन संख्या 09428 राजगीर-अहमदाबाद स्पेशल 11 नवंबर को राजगीर से प्रस्थान करेगी।

पश्चिम रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 09427 अहमदाबाद-राजगीर अनारक्षित सुपरफास्ट स्पेशल 10 नवंबर को अहमदाबाद स्टेशन से रात 00.55 बजे रवाना होगी और अगले दिन यानी 11 नवंबर को सुबह 11.45 बजे राजगीर पहुंचेगी। इस तरह गुजरात से बिहार जाने वाले यात्रियों को त्योहार के दौरान एक अतिरिक्त रेल विकल्प मिलेगा। वहीं, वापसी की दिशा में ट्रेन संख्या 09428 राजगीर-अहमदाबाद स्पेशल 11 नवंबर 2026 को राजगीर स्टेशन से दोपहर 14.45 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन अगले दिन 12 नवंबर को रात 23.25 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में निर्धारित समय के अनुसार संचालन किया जाएगा।

इस विशेष ट्रेन का मार्ग गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई महत्वपूर्ण शहरों तथा रेलवे स्टेशनों को जोड़ता है। इससे केवल अहमदाबाद और राजगीर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को ही नहीं, बल्कि रास्ते में पड़ने वाले विभिन्न शहरों के यात्रियों को भी लाभ मिलेगा। पश्चिम रेलवे ने ट्रेन को दोनों दिशाओं में कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव दिया है, ताकि अलग-अलग क्षेत्रों के लोग अपनी सुविधानुसार यात्रा कर सकें।

अहमदाबाद से रवाना होने के बाद ट्रेन आणंद, छायापुरी, गोधरा और दाहोद स्टेशनों पर ठहरेगी। इन स्टेशनों से गुजरात के मध्य और पूर्वी हिस्सों के यात्रियों को बिहार की ओर जाने के लिए अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। इसके बाद ट्रेन राजस्थान में प्रवेश करेगी और रतलाम, भवानी मंडी, रामगंज मंडी तथा कोटा होते हुए आगे बढ़ेगी। इन स्टेशनों पर ठहराव से मध्य प्रदेश और राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को भी इस विशेष सेवा का लाभ उठाने का अवसर मिलेगा।

राजस्थान में आगे बढ़ते हुए ट्रेन सवाई माधोपुर, हिण्डौन सिटी और बयाना स्टेशनों पर रुकेगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश में इंदगाह आगरा, टूंडला, गोविंदपुरी और सुबेदारगंज स्टेशनों पर इसका ठहराव निर्धारित किया गया है। इन स्टेशनों के माध्यम से आगरा, कानपुर और प्रयागराज सहित आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को भी यात्रा की सुविधा मिलेगी। लंबी दूरी की इस ट्रेन में विभिन्न प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव रखे जाने से यात्रियों को अपने गंतव्य के नजदीक उतरने का विकल्प उपलब्ध होगा।

इसके बाद ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंचेगी और बिहार की ओर आगे बढ़ेगी। बिहार में बक्सर, आरा और दानापुर के बाद पटना तथा पटना साहिब स्टेशन पर भी ठहराव दिया गया है। इसके अलावा बख्तियारपुर, बिहार शरीफ और नालंदा स्टेशनों पर रुकते हुए ट्रेन राजगीर पहुंचेगी। इस मार्ग से बिहार के कई महत्वपूर्ण धार्मिक, सांस्कृतिक और शहरी क्षेत्रों के यात्रियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। वापसी में राजगीर से अहमदाबाद आने वाली ट्रेन भी इन्हीं निर्धारित स्टेशनों पर ठहरेगी।

छठ पूजा बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकपर्वों में शामिल है। इस अवसर पर देश के अलग-अलग हिस्सों में काम करने वाले लोग अपने परिवारों के साथ त्योहार मनाने के लिए अपने गृह नगर और गांव पहुंचते हैं। गुजरात के अहमदाबाद, आणंद, गोधरा और आसपास के औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग रहते और काम करते हैं। ऐसे में छठ के समय इन क्षेत्रों से बिहार जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है। नियमित ट्रेनों में आरक्षण उपलब्ध नहीं होने या सामान्य डिब्बों में अत्यधिक भीड़ होने के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

एमडीएल के दिवाली मेले में 13 स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को मिला बाजार

मुंबई। सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने और स्वयं सहायता समूहों से जुड़े लोगों को अपने उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) की ओर से दो दिवसीय दिवाली मेले का आयोजन किया गया। तीन महीने के निवारक सतर्कता अभियान के अंतर्गत आयोजित यह मेला 3 और 4 नवंबर 2026 को लगाया गया। इसमें 13 स्वयं सहायता समूहों ने हिस्सा लेकर अपने उत्पादों के स्टॉल लगाए। मेले में हस्तकला, गृह सजावट की वस्तुएं, कपड़े, पेंटिंग और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ आकर्षण का केंद्र रहे। एमडीएल के कर्मचारियों और स्थानीय निवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए इन उत्पादों की खरीदारी की और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों का हौसला बढ़ाया।

एमडीएल की यह पहल केवल दीपावली के अवसर पर खरीदारी और उत्सव तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसके माध्यम से छोटे उत्पादकों, ग्रामीण कारीगरों और स्वयं सहायता समूहों को अपने हुनर तथा मेहनत से तैयार वस्तुओं को व्यापक स्तर पर प्रदर्शित करने का अवसर भी मिला। अक्सर स्थानीय स्तर पर काम करने वाले कारीगरों और महिला समूहों के सामने अपने उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचाने की चुनौती रहती है। ऐसे आयोजनों से उन्हें सीधे ग्राहकों से जुड़ने, अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता और उपयोगिता बताने तथा बिक्री के नए अवसर तलाशने में मदद मिलती है।



इस मेले में शामिल 13 स्वयं सहायता समूहों ने अलग-अलग तरह के उत्पादों के स्टॉल लगाए थे। हस्तनिर्मित वस्तुओं और पारंपरिक शिल्प से तैयार सामग्री ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। वहीं, घरों को सजाने के लिए उपयोगी वस्तुओं, आकर्षक पेंटिंग और कपड़ों की भी अच्छी मांग देखने को मिली। खाद्य पदार्थों के स्टॉल भी मेले का प्रमुख आकर्षण रहे। विभिन्न समूहों ने अपनी स्थानीय कला, पारंपरिक कौशल और रचनात्मकता के आधार पर तैयार किए गए उत्पादों को प्रदर्शित किया। आगंतुकों को एक ही स्थान पर अलग-अलग प्रकार की वस्तुएं देखने और खरीदने का अवसर मिला।

एमडीएल के कर्मचारियों के साथ आसपास के क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों ने भी मेले में भाग लिया। लोगों ने स्वयं सहायता समूहों के स्टॉल पर पहुंचकर उत्पादों की जानकारी ली और अपनी पसंद के अनुसार खरीदारी की। इस सहभागिता से समूहों को अपने उत्पादों के प्रति ग्राहकों की पसंद और जरूरतों को समझने का अवसर मिला। साथ ही, उन्हें यह जानने में भी मदद मिली कि बाजार में किस प्रकार के उत्पादों की मांग अधिक है और उनकी गुणवत्ता, डिजाइन तथा प्रस्तुति में किस तरह सुधार किया जा सकता है। इस प्रकार मेले ने उत्पादों की बिक्री के साथ अनुभव और बाजार की समझ विकसित करने का मंच भी उपलब्ध कराया।

दिवाली मेले का उद्घाटन एमडीएल के निदेशक (संचालन) बीजू जॉर्ज ने किया। इस अवसर पर कंपनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी हरि नारायण जांगिड़, निदेशक (सीपी एंड पी) कमांडर वासुदेव पुराणिक, निदेशक (वित्त) रुचिर अग्रवाल और निदेशक (तकनीकी) कमांडर शैलेश जामगांवकर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित रहे। वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी ने आयोजन के महत्व को रेखांकित किया। मेले के दौरान स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को अपने उत्पादों के बारे में जानकारी देने और आगंतुकों से सीधे संवाद करने का अवसर मिला। यह आयोजन एमडीएल की ओर से चलाए जा रहे तीन महीने के निवारक सतर्कता अभियान का हिस्सा था। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के निर्देशों के अनुरूप कंपनी ने 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह भी मनाया था। इस अभियान का उद्देश्य संगठनात्मक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और सतर्कता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसके साथ ही सामुदायिक विकास से जुड़ी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना भी इस पहल का महत्वपूर्ण पक्ष रहा। दिवाली मेले के आयोजन के माध्यम से एमडीएल ने सतर्कता अभियान को सामाजिक सहभागिता और स्थानीय समुदायों के सहयोग से जोड़ने का प्रयास किया। आमतौर पर सतर्कता अभियान को सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में भ्रष्टाचार की रोकथाम, नियमों के पालन तथा कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि, एमडीएल ने इस अभियान के तहत सामुदायिक भागीदारी को भी महत्व दिया। स्वयं सहायता समूहों को मंच उपलब्ध कराना इसी सोच का हिस्सा है। इससे एक ओर छोटे स्तर पर काम करने वाले उत्पादकों को अपने उत्पादों की बिक्री का अवसर मिलता है, वहीं दूसरी ओर संस्थान के कर्मचारी और स्थानीय नागरिक स्थानीय हस्तशिल्प तथा घरेलू उत्पादों को प्रोत्साहित करने में भागीदार बनते हैं।

स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों ने अपने उत्पादों को इतने व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचाने का अवसर देने के लिए एमडीएल के प्रति आभार व्यक्त किया। उनका कहना था कि इस तरह के आयोजन से उन्हें अपने काम को पहचान दिलाने और नए ग्राहकों तक पहुंचने में मदद मिलती है।

नाशिक रोड स्टेशन पर यात्री के बैग से 38 पैकेट पटाखे बरामद

भुसावल। दीपावली और छठ पूजा के दौरान रेलवे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मध्य रेल के भुसावल मंडल की ओर से चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के तहत नाशिक रोड रेलवे स्टेशन पर बड़ी कार्रवाई की गई। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने ट्रेन में अवैध रूप से पटाखे ले जा रहे एक यात्री को पकड़ा। उसके पास से 38 पैकेट पटाखे बरामद किए गए, जिनकी पैकेटों पर अंकित कुल कीमत 19,356 रुपये बताई गई है। रेलवे नियमों के उल्लंघन के आरोप में यात्री के खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की गई। रेलवे के अनुसार, यह घटना 7 नवंबर 2026 की है। नाशिक रोड रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर आरपीएफ के जवान यात्री सुरक्षा ड्यूटी में तैनात थे। इसी दौरान कांस्टेबल विकास साठे की नजर एक व्यक्ति पर पड़ी, जो नीले रंग के बड़े प्लास्टिक बैग में कुछ सामान लेकर जा रहा था। बैग में पटाखे होने का संदेह होने पर जवान ने उसे रोककर पूछताछ की और सामान की जांच की। जांच के दौरान बैग से पटाखों के 38 पैकेट बरामद हुए।

पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम गिरीश संजय कुमावत (32) और निवासी गारखेडा, जिला छत्रपति संभाजीनगर बताया। आरपीएफ ने उसे आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट पर लाया।



वहां उपनिरीक्षक ए.के. तिवारी ने दो स्वतंत्र पंचों की मौजूदगी में उससे पूछताछ की और बरामद पटाखों के संबंध में पंचनामा तैयार कराया। इस दौरान यात्री ने स्वीकार किया कि वह पटाखे ट्रेन में लेकर जा रहा था। हालांकि, उसके पास रेलगाड़ी में पटाखे ले जाने से संबंधित कोई वैध अनुमति नहीं थी।

रेलवे सुरक्षा बल ने बरामद पटाखों की पैकेटों पर अंकित कीमत के आधार पर उनका कुल मूल्य 19,356 रुपये बताया। रेलवे नियमों के अनुसार, ज्वलनशील और खतरनाक सामग्री को बिना निर्धारित अनुमति रेलगाड़ी में ले जाना यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है। पटाखों में मौजूद विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थ के कारण आग लगने या अन्य दुर्घटना की आशंका रहती है। विशेष रूप से त्योहारों के दौरान ट्रेनों और स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ अधिक होने से ऐसी लापरवाही के परिणाम गंभीर हो सकते हैं।

आरपीएफ ने गिरीश संजय कुमावत के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत मामला दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की। इसके बाद उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 35(3) के तहत नोटिस देकर छोड़ दिया गया। मामले में रेलवे सुरक्षा बल ने नियमानुसार कार्रवाई पूरी की।

मध्य रेल का भुसावल मंडल दीपावली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए स्टेशनों और ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दे रहा है। इसी क्रम में संदिग्ध सामान की जांच, प्रतिबंधित वस्तुओं की आवाजाही पर निगरानी और यात्रियों को सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। रेलवे प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी यात्री ऐसी ज्वलनशील या खतरनाक सामग्री लेकर ट्रेन में सफर न करे, जिससे अन्य यात्रियों की जान-माल को खतरा हो।

रेलवे सुरक्षा बल की इस कार्रवाई ने एक बार फिर त्योहारों के दौरान रेल यात्रा में सुरक्षा नियमों के पालन की आवश्यकता को सामने रखा है। रेलवे प्रशासन यात्रियों से अपील करता है कि वे पटाखे और अन्य खतरनाक ज्वलनशील वस्तुएं ट्रेन में लेकर यात्रा न करें तथा किसी भी संदिग्ध सामान या गतिविधि की जानकारी तुरंत रेलवे सुरक्षा कर्मियों को दें।

रॉकेट की चिंगारी से अवैध पार्किंग में भड़की आग, छह वाहन राख

विरार। वसई-विरार क्षेत्र में आग लगने की घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को आग लगने की तीन घटनाओं के बाद सोमवार को नालासोपारा पूर्व के ओसवाल नगरी के पास एक अवैध वाहन पार्किंग में आग लग गई। इस घटना में वहां खड़े छह वाहन जलकर पूरी तरह राख हो गए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि दमकलकर्मियों ने समय रहते आग को आसपास के क्षेत्र में फैलने से रोक लिया और कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। यह घटना सोमवार दोपहर करीब 12 बजे की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दीपावली के दौरान छोड़े जा रहे पटाखों में से एक रॉकेट की चिंगारी पार्किंग में खड़े वाहनों पर जा गिरी। इसके बाद वाहनों में आग लग गई और देखते ही देखते लपटें तेज हो गईं। पार्किंग में एक साथ कई वाहन खड़े होने के कारण आग तेजी से फैलने की आशंका बनी रही। घटना की जानकारी मिलने पर दमकल विभाग की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू किया। काफी प्रयासों के बाद आग पर नियंत्रण पाया जा सका, लेकिन तब तक छह वाहन बुरी तरह जल चुके थे।

घटना के बाद आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक, जिस स्थान पर वाहनों की पार्किंग की जाती है, वहां प्रत्येक रविवार को संडे बाजार भी लगता है। इस बाजार में बड़ी संख्या में दुकानदार अपनी दुकानें लगाते हैं और आसपास के क्षेत्रों से लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं। बाजार के दिनों में यहां काफी भीड़ रहती है। ऐसे में यदि आग की घटना रविवार को बाजार लगने के दौरान होती, तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी। वाहनों में लगी आग ने स्थानीय नागरिकों के बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है।



स्थानीय लोगों के अनुसार, जिस जमीन पर अवैध पार्किंग और संडे बाजार संचालित हो रहा है, वह फ्लाईओवर निर्माण के लिए आरक्षित बताई जा रही है। इसके बावजूद यहां नियमित रूप से वाहनों को खड़ा किया जाता है और रविवार को बाजार भी लगाया जाता है। नागरिकों का कहना है कि इस तरह के स्थान पर बिना पर्याप्त सुरक्षा इंतजामों के वाहन पार्किंग और बाजार का संचालन करना दुर्घटनाओं को न्योता देने जैसा है। खासकर त्योहारों के दौरान पटाखों से निकलने वाली चिंगारियों के कारण आग लगने का खतरा और बढ़ जाता है।

इस मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता राकेश सिंह ने पहले भी संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को लिखित शिकायत दी थी। उन्होंने वसई-विरार महानगरपालिका आयुक्त, प्रभाग समिति 'बी' की सहायक आयुक्त अलका खैरे, मीरा-भायंदर-वसई-विरार पुलिस आयुक्त, स्थानीय वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय जाधव और भाजपा के स्थानीय नगरसेवक निलेश चौधरी को अवैध पार्किंग तथा संडे बाजार के संचालन के संबंध में शिकायत भेजी थी। राकेश सिंह का आरोप है कि बार-बार शिकायत किए जाने के बावजूद संबंधित विभागों की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना है कि यदि समय रहते इस स्थान से अवैध पार्किंग और बाजार को हटाने की कार्रवाई की गई होती, तो ऐसी घटनाओं की आशंका को कम किया जा सकता था।

वहीं, स्थानीय नागरिकों ने भी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद न तो अवैध पार्किंग को हटाया गया और न ही संडे बाजार के संचालन पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाया गया। लोगों का कहना है कि सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े इस मामले में संबंधित विभागों को गंभीरता दिखानी चाहिए, क्योंकि बाजार में बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही रहती है। यदि आग की लपटें आसपास की दुकानों या भीड़भाड़ वाले हिस्से तक पहुंच जातीं, तो बड़ा हादसा हो सकता था।

इस संबंध में वसई-विरार महानगरपालिका के प्रभाग 'बी' के अतिक्रमण विभाग के अधिकारी हर्षल राउत से संपर्क कर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। ऐसे में अवैध पार्किंग और संडे बाजार को लेकर उठाए गए सवालों पर महानगरपालिका प्रशासन का पक्ष सामने नहीं आ सका।

फिलहाल आग लगने की इस घटना ने एक बार फिर क्षेत्र में अवैध पार्किंग, अतिक्रमण और सार्वजनिक स्थानों पर लगने वाले बाजारों की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। छह वाहनों के जलने से वाहन मालि